साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026
हम दिखाएंगे आईना...
वर्ष : 02 अंक : 06 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए
www.shaharsatta.com

पेज 10 में...
अलविदा सुरों की रानी

पेज 04 में...
11 बांधों से सिंचाई के लिए मिल रहा पानी

तीनों की पसंद ब्लैक...

रमन को पजेरो, बघेल को फॉर्च्यूनर, साय को भा गई स्कॉर्पियो-एन

- CM के काफिले में 9 नई बुलेटप्रूफ एसयूवी स्कॉर्पियो एन ब्लैक
- भूपेश बघेल कार्यकाल की फार्च्यूनर कारकेड से कर दी गई बाहर
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव बोले-पुरानी गाड़ियां रास्ते में हो जाती थी बंद
- बघेल-साय शासनकाल में तक़रीबन 900 एसयूवी वाहनों की खरीदी
- 6 माह के अंदर ली गईं 40 बीपी गाड़ियां एक गाड़ी की कीमत 75 लाख

सियासी जमात भले ही अलहदा हो, लेकिन रंग का मिज़ाज़ एक सामान ही होता है 'काला' ! बड़े ही संघर्षो के बाद बने छत्तीसगढ़ राज्य में लीडरान को भी कमोबेश 'काला' ही पसंद है। हालांकि काला रंग आमतौर पर बुरा माना जाता है। मज़े की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के तीन सूबा-ऐ-सदरों तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अपने लिए ब्लैक पजेरो, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली फॉर्च्यूनर तो सरल सहज और सादगी से लबरेज शख्सियत वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को करिया स्कॉर्पियो-एन गाड़ी मन भा गई। खर्च की चिंता नहीं, पुलिस थानों के पास कैसी खस्ताहाल गाड़ियां हैं इससे भी किसी को मतलब नहीं ! बस बंगले से हेलीपेड तक और फिर हैलीकॉप्टर में फुर्र से उड़कर जनहित में सुशासन करने वालों की गाड़ियां बड़ी जल्दी कंडम हो जा रही हैं।

शहर सत्ता/रायपुर। योजना एवं प्रबंध, और पुराना पीएचक्यू स्थित वीवीआईपी वहां सुरक्षा के भरोसे ही भूपेश और साय कार्यकाल में महज चंद महीनों में ही तक़रीबन 900 एसयूवी वाहनों की खरीदी शासन द्वारा की गई है। इस फिजूल खर्ची में महज कुछ ही लॉ एन ऑर्डर तथा अनजान खतरों से सुरक्षा के मद्देनजर ली गई हैं बाकि गाड़ियां तो महज बजट खपाने का प्रयास है। भूपेश बघेल के वक्त लग्जरी एसयूवी और बीपी यानि की बुलेट प्रुफ 200 गाड़ियां ली गई थीं। साय शासन काल में यह आंकड़ा 600 पार हो गया है। भूपेश कार्यकाल में स्कॉर्पियो खरीदी गई, लेकिन वह कंडम हो गई और बहुत बाद में उसे विभागों को आवंटित किया गया। इसी तरह कानून व्यवस्था, सुरक्षा के नाम पर खरीदी गई गाड़ियां मंत्री स्टाफ को सवारी के लिए दे दी गई है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के पहले रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में ही अफसरों को गाड़ियां सेकेंड हेंड मिली है। पीसीआर और थानों में पेट्रोलिंग अब भी खस्ताहाल हैं और पुरानी सूमो, बोलेरो के भरोसे पुलिसिंग है। जबकि करोड़ों रूपये खर्च कर धड़ल्ले से ली जा रही लग्जरी तेज रफ़्तार गाड़ियां माननियों के स्टाफ को दी गई हैं।

सुशासन में 400 नई एसयूवी गाड़ियां, जिसमें सीएम को 9 बीपी गाड़ी

अभी 8 माह में पूर्व और वर्तमान कार्यकाल की 4 से 5 सौ एसयूवी ली गई है। इसमें सीएम कारकेड समेत अन्य के लिए 9 बीपी (बुलेट प्रुफ) गाड़ी हैं। सुरक्षा और ख़ुफ़िया विभाग से लेकर आईजी, स्पीकर एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों को गाड़ियां अलॉट की गई हैं।

कांग्रेस शासनकाल में खरीदी गईं थीं 200 से ज्यादा एसयूवी

तात्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में आनन-फानन में 2 से 3 सौ नॉर्मल बोलेरो की खरीदी की गई थी। उक्त सभी गाड़ियां काफी समय बाद अभी बाटी गई। क्यों 2 से 3 सौ नॉर्मल बोलेरो ली गई और ये सभी किसके लिए थी ये जांच का विषय है।

ईओडब्ल्यू-एसीबी जांच से होंगे चौंकाने वाले खुलासे

वाहन खरीद और उसके आवंटन की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी से करवाई जानी चाहिए तो इसके पीछे की वजह सब साफ हो जाएगी।

किसी को भी देशी गाड़ियां नहीं बलकी आधुनिक महंगी गाड़ियां चाहिए। कुछ मंत्रियों के पास तो करोड़ों रूपये की विदेशी ब्रांड मॉडल की गाड़ियां होने के बाद भी उन्हें सरकारी वाहन और पेट्रोल पर ही सवारी करना पसंद है। महज देसी प्रेम दिखावे के लिए ही है। महेंद्रा की स्कॉर्पियो सीरीज, बोलेरो आदि बल्क में खरीदी गई है। इसका फैसला भी सिर्फ ड्राइवर, स्टेनो और मझोले स्तर के अफसर वाहन कंपनियों से मिलकर करते रहे हैं। पुलिस, वीआईपी सुरक्षा और फारेस्ट में ही क्यों गाड़ियां कंडम हो जा रहीं यह बड़ा सवाल है।

गाड़ियों की खरीदी का बड़ा खेल छोटों के जिम्मे

देखा जाये तो बजट राशि लैप्स नहीं हो करके आखरी समय यानि कि मार्च से पहले ऐसी ही खरीदी के कई उदाहरण मिलते हैं। सरकारी विभागों, वीआईपी काफिले और मंत्री-विधायकों के नाम पर बिचौलिए खीर खा रहे हैं। गाड़ियों की जरुरत और किसी खास कंपनी की गाड़ियां लेने के लिए ड्राइवर, स्टेनो, और अधिकारी स्तर के लोग तय करते हैं। योजना प्रबंध और एमटीओ स्तर पर सरकारी गाड़ियों की खरीद, इनमें पेट्रोल-डीजल की पर्ची, कंडम वाहनों के पार्ट्स और मेंटेनेंस के नाम पर बड़ा खेल छोटे लोग कर रहे हैं।

ADITYA MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE (PROVISIONING)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO		[illegible]	[illegible]
ADITYA MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE (PROVISIONING)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO		[illegible]	[illegible]
ADITYA MOTORS	[illegible]	Mahindra & Mahindra Financial Servic	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MARAZZO		[illegible]	[illegible]
ADITYA MOTORS	[illegible]	Mahindra & Mahindra Financial Servic	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MARAZZO		[illegible]	[illegible]
ADITYA MOTORS	[illegible]	Mahindra & Mahindra Financial Servic	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MARAZZO		[illegible]	[illegible]
ADITYA MOTORS	[illegible]	Mahindra & Mahindra Financial Servic	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MARAZZO		[illegible]	[illegible]
[illegible] AUTOMOBILES PVT. LTD.	[illegible]	SR. SUPERINTENDENT OF POST OFFICES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO		[illegible]	[illegible]
[illegible] PVT. LTD.	[illegible]	Sr. Superintendent of Post Offices	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO		[illegible]	[illegible]
PARAMOUNT AUTOMOBILES PVT LTD	[illegible]	SR. SUPERINTENDENT OF POST OFFICES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]
RALAS MOTORS	[illegible]	AIG OF POLICE/PLANNING & PROVISION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BOLERO-N		[illegible]	[illegible]

RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532106296	12/30/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532106297	12/30/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532106298	12/30/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532106299	12/30/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532106944	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532106945	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532106946	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107375	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107376	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107377	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107378	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107379	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107380	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107381	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107382	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107383	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107384	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107385	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107386	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107387	12/31/2025
RALAS MOTORS	A0208161	AIG OF POLICE (PLANNING & PROVISION	BOLERO-NP	7532107388	12/31/2025

प्रमुख बिंदु

1. एक नॉर्मल स्कॉर्पियो की कीमत 15 लाख, अब तक 200 गाड़ियां ली गईं
2. 6 माह के अंदर ली गईं 40 बीपी गाड़ियां एक गाड़ी 75 लाख की
3. भूपेश के समय खरीदी गाड़ी की डिलिवरी लेट हुई और बटालियन में खड़ी रहीं
4. रालास और शिवनाथ मोटर से सभी महेंद्रा कंपनी की सभी गाड़ियां पर्चेस की गईं
5. भूपेश के समय तकरीबन 4 करोड़ की साय के टाइम तकरीबन 12 से 13 करोड़ की
6. बोलेरो नियो, स्कार्पियो एन, नॉर्मल, प्लस और क्लासिक समेत बीपी गाड़ियां खरीदी गईं
7. बीपी यानि कि बुलेट प्रुफ गाड़ी तकरीबन 24 करोड़ की है
8. पीसीसीएफ ने फॉरेस्ट के लिए 300 बोलेरो और 30 बसे 25-26 मार्च बजट से पहले लिया

गाड़ी की खासियत

ये सभी गाड़ियां बुलेटप्रूफ हैं, यानी कि इन्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि इनमें गोलियों, बम धमाकों और ग्रेनेड के हमलों का असर ना पड़े

इन सभी गाड़ियों को एक खास तरीके के मजबूत बैलिस्टिक स्टील से तैयार किया गया है।

सभी गाड़ियां एडास सिस्टम पर काम करती हैं।

एडास सिस्टम सेंसर से लैस होने की वजह से चलते-चलते ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने और लेन बदलने में मदद मिलती है।

इनकी खिड़कियों में मोटी कांच की परतें लगाई गई हैं, जो AK-47 जैसी राइफलों का सामना भी कर सकती हैं।

साथ ही जब काफिले में कई गाड़ियां होती हैं, तो आगे वाली कार से सही दूरी बनाए रखने में भी मदद मिलती है।

ये सभी गाड़ियां 7 सीटर हैं, जिनमें आगे-पीछे कैमरा और सेंसर लगाया गया है।

कार के अंदर बैठे लोगों की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग मौजूद हैं और लंबी दूरी को समय पर पूरा करने के लिए दमदार इंजन है।

फर्जी ई-चालान से ठगी का खतरा बढ़ा

अलर्ट जारी, अफसर बोले- केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही करें भुगतान

शहरसत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर में इन दिनों फर्जी ई-चालान मैसेज और नकली वेबसाइट/एप्लीकेशन के जरिए साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। साइबर अपराधी लोगों को चालान के नाम पर डराकर उनसे ऑनलाइन पेमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक, ठग अनजान नंबरों से SMS या व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजते हैं, जिसमें वाहन का लंबित चालान बताकर तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है। कई बार ये लिंक बिल्कुल असली वेबसाइट जैसे दिखते हैं, जिससे लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं और अपनी निजी जानकारी या बैंक डिटेल साझा कर देते हैं।

अधिकृत वेबसाइट-ऐप से करें भुगतान

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि, वाहन के पेंडिंग ई-चालान का भुगतान केवल भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ या NextGen mParivahan App के जरिए ही करना चाहिए। इन प्लेटफॉर्म पर भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता, जबकि थर्ड पार्टी एप या वेबसाइट पर भुगतान करने से अतिरिक्त चार्ज भी देना पड़ सकता है।

अंजान नंबरों से आए लिंक को ना करें क्लिक

पुलिस ने नागरिकों को कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। अंजान नंबरों से आए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और केवल अधिकृत सेंडर आईडी जैसे B V - VAAHAN-G, BT-VAAHAN-G, BH-VAAHAN-G, BM-VAAHAN-G या BZ-VAAHAN-G से आए संदेशों पर ही भरोसा करें। इसके अलावा वेबसाइट की स्पेलिंग ध्यान से जांचें, क्योंकि नकली वेबसाइट असली जैसी दिख सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी स्थिति में अपना OTP किसी के साथ साझा न करें, भले ही सामने वाला खुद को अधिकारी ही क्यों न बताए। साथ ही किसी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत भुगतान करने से बचें और पहले चालान को अधिकृत प्लेटफॉर्म पर वेरिफाई जरूर करें।

धोखाधड़ी होने पर करें शिकायत- पुलिस

यदि किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही अपने बैंक को तुरंत सूचित करें, ताकि ट्रांजैक्शन को रोका जा सके।

रायपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल में NextGen mParivahan App इंस्टॉल करें और इसी के जरिए ई-चालान चेक व भुगतान करें। यह सुरक्षित प्लेटफॉर्म है और इसमें वाहन से जुड़े सभी दस्तावेज भी डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

जाम क्लियर कराने बाइक क्यूआरटी तैयार

शहरसत्ता/रायपुर। राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या होने पर त्वरित राहत पहुंचाने के लिए यातायात पुलिस की 10 बाइक क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) तैयार कर ली गई है। यह टीम सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और शाम को 17 से 22 बजे के मध्य सेवाएं देगी। आईटीएमएस कंट्रोल रूम से पुलिस पहले ही गूगल मैप के जरिये पूरे शहर की ट्रैफिक पर नजर रख रही है। जाम में फंसने वाले लोगों के लिए एक मोबाइल नंबर 9479210632 जारी किया गया है। जिस पर लोग कॉल करके या वाट्सएप पर मैसेज या फोटो-वीडियो भेजकर सूचनाएं दे सकेंगे। ट्रैफिक अफसरों डीसीपी ट्रैफिक एंड प्रोटोकॉल विकास कुमार ने कहा कि सड़कों पर हादसे में कमी लाने के लिए प्रयास जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस अब ई-चालान ही कर रही है। आने वाले दिनों में जुर्माना या समझौता राशि का भुगतान भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। इसके लिए एसबीआई से पीओएस मशीनों व अन्य सिस्टम की मांग की गई है। पुलिस की कोशिश पांच मिनट के भीतर संबंधित चौराहों व सड़कों पर पहुंचकर समस्या का समाधान करने की है।

5 मिनट में पहुंचेंगे, हादसे रोकने के भी प्रयास जारी फाइन भी लेंगे ऑनलाइन

रायपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाते 155 लोग पकड़ाए, लाइसेंस होंगे सस्पेंड

शहरसत्ता/रायपुर। रायपुर में सड़क हादसों की संख्या में कमी आए। वाहन ड्राइवर सुरक्षित घर पहुंचे, इसलिए कमिश्नरेट के अधिकारी शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शनिवार को लेट नाइट चेकिंग अभियान चलाकर पुलिसकर्मियों ने 155 वाहन ड्राइवरों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़ा है। इन वाहनों को सीज किया गया है। वाहन चालक कोर्ट में जुर्माना जमा कर पुलिसकर्मियों से अपनी गाड़ी वापस लेंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जो वाहन चालक शराब के नशे में मिले है, उनके लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए परिवहन अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा।

रात 11 बजे से 1 बजे के बीच चेकिंग

यातायात और प्रोटोकॉल उपायुक्त विकास कुमार के नेतृत्व में यह अभियान शहर के 9 अलग-अलग स्थानों पर चलाया गया। रात 11 बजे से 1 बजे के बीच लगाए गए चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिसकर्मियों ने ब्रीथ एनालाइजर की मदद से ड्राइवरों की जांच की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े गए।

2133 से ज्यादा लोग पकड़ाए

पुलिस के मुताबिक, साल 2026 में अब तक मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (शराब पीकर वाहन चलाना) के तहत 2133 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा रायपुर जिले के इतिहास में किसी भी पूरे साल की कार्रवाई से अधिक बताया जा रहा है। जिससे यह साफ है कि पुलिस इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि, इस तरह के अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान बचाना है। शराब के नशे में वाहन चलाना सबके लिए खतरनाक है।

ट्रैफिक-पुलिस की कस्टडी से मेटाडोर चोरी

शहरसत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक थाना फाफाडीह के ठीक सामने खड़े जब्त मेटाडोर को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। अब पुलिस की कस्टडी में रखे वाहन भी चोरी हो रहे हैं। जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, मेटाडोर क्रमांक CG 12 BH 3683 को 7 अप्रैल को प्रतिबंधित मार्ग में प्रवेश करने पर जब्त किया गया था। यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को फाफाडीह थाने के सामने खड़ा कर दिया था। वाहन ड्राइवर को आवश्यक दस्तावेज के साथ 8 अप्रैल की सुबह 11 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।

दो दिन तलाश के बाद FIR दर्ज

बताया जा रहा है कि, वाहन दो दिन तक थाने के सामने ही खड़ा रहा, लेकिन 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात अज्ञात चोर उसे मौके से लेकर फरार हो गए। पुलिसकर्मियों ने दो दिन तक गाड़ी की तलाश की, गाड़ी नहीं मिली तो फिर गंज थाने में लिखित शिकायत दी है। यातायात थाना फाफाडीह में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (ASI) केशरी कुमार साहू ने गंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। संदिग्धों की पहचान और वाहन की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई है।

पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर जब्त वाहन थाने की निगरानी में सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन इस तरह की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

हाईप्रोफाइल कस्टमर देते थे ऑर्डर, दिल्ली से कुरियर के जरिए पहुंचता था

रायपुर में पकड़ाया 'ओशिएन ग्रोथ' गांजा

शहरसत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर में 1 करोड़ प्रति किलो बिकने वाला गांजा पकड़ाया है। हाईप्रोफाइल कस्टमर की डिमांड पर दिल्ली से कुरियर के जरिए यहां 'ओशिएन ग्रोथ' गांजे की सप्लाई हो रही थी। पुलिस को शक होने पर रेड मारकर कार्रवाई की। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है, जो शंकर नगर में किराए के मकान से रह रहा था, यहां गांजा मंगवाकर बेचता था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। आरोपी रितिक पसरिचा (26) कटोरा तालाब में एक ग्राहक को जैसे ही गांजा देने पहुंचा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके कब्जे से 114 ग्राम ओजी गांजा मिला। ओशिएन ग्रोथ गांजे की मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, यह समुद्री इलाके में पानी में उगता है।

ओशियन ग्रोथ गांजा क्या है?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गांजा ओजी ग्रेड (ओशियन ग्रोथ) का है, यह हाइड्रोपोनिक है और इसे जमीन पर नहीं सिर्फ पानी में उगाया जा सकता है। इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पानी में पोषक तत्वों के साथ यह उगता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए प्रति किलो तक है।

दिल्ली से कुरियर के जरिए होती थी सप्लाई

जानकारी के मुताबिक, रितिक पसरिचा (26) दिल्ली का रहने वाला है, वह बार सिंगर भी है। रायपुर में वह म्यूजिक एलबम बनाने के बहाने शंकर नगर स्थित अशोका हाईट्स में किराए के मकान में रह रहा था। दिल्ली से कुरियर के जरिए यहां गांजे की डिलवरी लेता था। सप्लायर कौन है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। रितिक शनिवार (11 अप्रैल) को कटोरा तालाब इलाके में ग्राहक को गांजा देने पहुंचा था। इसकी जानकारी पुलिस को मिली, तो उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसके बैग की तलाशी में OG गांजा समेत, मोबाइल और सामान्य गांजा भी मिला है। सभी की कीमत 3.62 लाख है।

रायपुर में खाद्य विभाग ने 1070KG पनीर किया नष्ट

शहरसत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर में पनीर बनाने वाली दो फैक्ट्रियों पर खाद्य-औषधि विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों के आधार पर की गई है। मौके पर पहुंची टीम ने फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण शुरू किया। फूड डिपार्टमेंट ने दोनों फैक्टियों से करीब 1060 किलो पनीर जब्त कर जमीन में दबाकर नष्ट किया। टीम ने दोनों जगह से पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। साथ ही मिल्क पाउडर के बोरे और तेल के कई टिन भी जब्त किए गए हैं। दरअसल, रायपुर में खाद्य एवं औषधि विभाग ने रविवार को पनीर की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर कार्रवाई की है। शिकायतों के बाद टीम ने भाटागांव के KLP डेयरी एंड प्रोडक्शन में दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने फैक्ट्री में साफ-सफाई की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री में गंदगी पाई गई, जिसके बाद डेयरी फैक्ट्री से 540 किलो पनीर जब्त कर नष्ट किया गया।

साप्ताहिक शहरसत्ता

राज्य के 11 बांधों से निस्तारी और सिंचाई के लिए दिया जा रहा पानी

राज्य के सिंचाई जलाशयों में अभी 67 प्रतिशत से अधिक जल भराव

शहरसत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में गर्मी से पूर्व कई क्षेत्रों में मांग के अनुसार पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य के 11 बांधों से नहर के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। निस्तारी और सिंचाई के लिए इन बांधों से पानी दिया जा रहा है। किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से नियंत्रित एवं चरणबद्ध रूप से जल छोड़ा जा रहा है।

गंगरेल बांध से नहरों के माध्यम से धमतरी एवं रायपुर क्षेत्रों में निस्तारी एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा रहा है। दुधावा जलाशय से मुख्य नहरों के जरिए पानी दिया जा रहा है। सोंदूर परियोजना से नहर प्रणाली के माध्यम से जल छोड़ा जा रहा है। कोडार जलाशय से लगभग 6.84 क्यूमेक्स जल नहरों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। परालकोट परियोजना से दाएं एवं बाएं तट नहरों के जरिए पानी वितरण किया जा रहा है। खरखरा, गोंडली, पिपरिया, सारोदा, जुमका, केदार नाला एवं अन्य जलाशयों से आवश्यकता अनुसार नहरों एवं स्लुइस गेट के माध्यम से जल छोड़ा जा रहा है, जिससे रबी फसलों की अंतिम सिंचाई एवं ग्रीष्मकालीन फसलों एवं निस्तारी के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके।

बांधों में 67 प्रतिशत से अधिक पानी

छत्तीसगढ़ राज्य के 12 वृहद एवं 34 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में इस वर्ष जल भराव की स्थिति काफी बेहतर है। वर्तमान में राज्य के कुल 46 प्रमुख सिंचाई जलाशयों में औसत रूप से 67.43 प्रतिशत जल भराव है, जो कि वर्ष 2025 में इसी अवधि में औसत रूप से 45.23 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 के 42 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। यह स्थिति बेहतर वर्षा, सुनियोजित जल प्रबंधन तथा जलाशयों के प्रभावी संचालन का परिणाम है।

मनियारी में 90, कोडार में 35 प्रतिशत जल भराव

12 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में वर्तमान में 68.19 प्रतिशत जल भराव है, जबकि वर्ष 2025 में यह 45.84 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 में 38.62 प्रतिशत था। प्रमुख वृहद जलाशयों में शामिल मनियारी जलाशय में 90.41 प्रतिशत, मुरूमसिल्ली में 86.85 प्रतिशत, खारंग में 84.99 प्रतिशत, दुधावा में 8454 प्रतिशत, रविशंकर सागर में 76.72 प्रतिशत, सोंदूर में 70.65 प्रतिशत एवं तांदुला में 66.19 प्रतिशत में जल उपलब्ध है। वहीं मिनीमाता बांगो जलाशय में 63.86 प्रतिशत तथा केलो में अभी 51.83 प्रतिशत जल भराव है। कोडार जलाशय में 35.45 प्रतिशत जल उपलब्ध है।

छिरपानी और खपरी में 92 प्रतिशत से अधिक जल भराव

इसी प्रकार राज्य की 34 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में वर्तमान में 63.38 प्रतिशत जल भराव है, जो कि वर्ष 2025 के 44.62 प्रतिशत एवं वर्ष 2024 के 45.38 प्रतिशत से अधिक है। मध्यम जलाशयों में छिरपानी जलाशय में 92 23 प्रतिशत, खपरी में 92 98 प्रतिशत, पिपरिया नाला में 89.69 प्रतिशत, गोंडली में 85.53 प्रतिशत, सुतियापाट में 79.82 प्रतिशत, सारोदा में 7757 प्रतिशत एवं कोसारटेडा में 77.46 प्रतिशत जल भराव अपने उच्च स्तर पर हैं।

छत्तीसगढ़ में 1 मई से जनगणना का पहला चरण

शहरसत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा। इस दौरान 'हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस' के तहत हर परिवार, मकान और बुनियादी सुविधाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कर्मचारी तय समय में घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे।

- **परिवार-मकान, वाहन समेत 33 सवाल पूछे जाएंगे, 7 स्टेप्स में ऑनलाइन भर सकेंगे जानकारी**

इस बार प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच लोग ऑनलाइन पोर्टल पर खुद भी अपने घर और परिवार की जानकारी भर सकेंगे। इसे सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा गया है। ऑनलाइन जानकारी भरने वालों को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसे बाद में कर्मचारियों को दिखाना होगा। जनगणना के इस चरण में मकान की स्थिति, उपयोग (रहवासी या व्यवसायिक), निर्माण की गुणवत्ता (कच्चा-पक्का), परिवारों की संख्या और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, बिजली, कुकिंग फ्यूल, इंटरनेट, टीवी-रेडियो जैसी सुविधाओं की भी जानकारी ली जाएगी। घर में कितने लोग रहते हैं और कौन-कौन से वाहन उपयोग होते हैं, यह भी दर्ज किया जाएगा।

हर घर बनेगा 'डिजिटल डॉट', 5 बड़े फायदे

इस बार हर मकान की जियो-टैगिंग कर उसे डिजिटल मैप पर दर्ज किया जाएगा। इसका फायदा कई स्तर पर मिलेगा। आपदा के समय राहत और बचाव तेजी से होगा, किस घर में कितने लोग हैं, तुरंत पता चलेगा। विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन में सटीक डेटा मिलेगा। शहरों में सड़क, स्कूल, अस्पताल और पार्क की बेहतर प्लानिंग हो सकेगी। पलायन और शहरीकरण की सही तस्वीर सामने आएगी। मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम हटाने में मदद मिलेगी।

ऐतिहासिक उपलब्धि : 10.30 किलो वजनी विशाल ट्यूमर को डॉक्टरों ने निकाला

शहरसत्ता/रायपुर। चिकित्सा, विशेषज्ञ टीम और संवेदनशील उपचार के माध्यम से जीवन को फिर से सामान्य बनाया जा सकता है। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ की चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है। यह उपलब्धि बताती है कि; हमारे सरकारी अस्पताल सक्षम हैं, हमारे डॉक्टर समर्पित हैं, हमारी चिकित्सा व्यवस्था निरंतर प्रगति कर रही है, और छत्तीसगढ़ अब केवल इलाज ही नहीं, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में नई मिसालें गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि सेवा, संवेदना, विज्ञान और समर्पण जब एक साथ आते हैं, तब चिकित्सा केवल उपचार नहीं रहती, वह किसी जीवन को पुनर्जन्म देने का माध्यम बन जाती है और इस केस में यकीनन ऐसा ही हुआ है।

दलहन और तिलहन फसलों के पंजीयन की मियाद बढ़ी, किसानों को राहत

- **समय से पहले पोर्टल लॉक होने से कई किसान नहीं करा पाए थे पंजीयन**

शहरसत्ता/रायपुर। प्रदेश में रकबा सत्यापन से वंचित हुए दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों के लिए पंजीयन की मियाद आगे बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत अब किसान आगामी 20 अप्रैल तक अपना गिरदावरी पोर्टल लॉक होने से पंजीयन नहीं कर पा रहे किसान पीएम आबोक्रा के तहत पंजीयन करा पाएंगे। राज्य शासन ने वंचित किसानों के दबाव के बाद समय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। किसान पंजीयन की मियाद खत्म होने से पहले ही गिरदावरी पंजीयन पोर्टल लॉक होने की शिकायतें थी।

इसके चलते बड़ी तादाद में किसानों का गिरदावरी डाटा इंद्राज नहीं हो पाया था। पूर्व में निर्धारित 31 मार्च की अवधि के पहले ही प्रविष्टि पोर्टल बंद कर दिया गया था। जिससे रबी उत्पादक किसानों का फसल रकबा दर्ज नहीं होने से नाराजगी भी सामने आ रही थी। दरअसल, प्रदेश के दलहन-तिलहन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करने पीएम आशा योजना के तहत फसल और रकबा सत्यापन कराने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसके अनुसार किसानों के लिए पंजीयन की अवधि अब 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। कृषि विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि बीते 31 मार्च को समाप्त हो चुके पंजीयन तिथि को आगे बढ़ाया गया है।

सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य

विभाग के संज्ञान में यह जानकारी आई कि रबी फसल के लिए की गई गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे अधूरा होने की वजह से उपार्जन के लिए फसल एवं रकबा सत्यापन में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए फसल और रकबा सत्यापन के लिए पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किसान को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इसे मान्य करते हुए फसल एवं रकबा सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

मनरेगा में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग

क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल

शहरसत्ता/रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने विभिन्न प्रमुख मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

97% सक्रिय श्रमिकों का ई-केवायसी पूर्ण

1 अप्रैल 2026 की स्थिति में राज्य ने 97 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-केवायसी पूर्ण कर लिया है, जिससे भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है। जिसके तहत प्रदेश के 58.16 लाख श्रमिकों का ई-केवायसी तथा 11.32 लाख निर्मित परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हुई है।

11,668 ग्राम पंचायतों में जीआईएस आधारित योजना

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से 11,668 ग्राम पंचायतों में 2,86,975 कार्यों की जीआईएस आधारित कार्ययोजना तैयार की गई है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक योजना निर्माण सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ ही मनरेगा कार्यस्थलों पर फेस ऑथेंटिकेशन आधारित एनएमएमएस (NMMS) प्रणाली के उपयोग से उपस्थिति की निगरानी अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है।

क्यूआर कोड से आमजन को सीधी जानकारी

ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से नागरिक, कार्यों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक सितंबर से अब तक लगभग 5 लाख से अधिक स्कैन दर्ज किए गए हैं। जिससे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

हर माह 7 तारीख को समाधान का मंच

प्रदेश में प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव के साथ "रोजगार दिवस" एवं "आवास दिवस" का आयोजन किया जा रहा है, जहां हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण एवं योजनाओं की जमीनी समीक्षा की जाती है।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

युद्ध की आग में चूल्हा बुझा

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलमार्ग के बंद होने से उपजा संकट अब गहराने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से भारत समेत कई देशों में ईंधन की उपलब्धता काफी कम हो गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। देश में सरकार की ओर से भले ही यह दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन हाल में व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर और विमान ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि संकट धीरे-धीरे अपने पांव पसार रहा है। सरकार देश भर में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में देरी को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे लोगों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इस बीच, पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को घरों में ईंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा गया है।

गौरतलब है कि ईरान तथा इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के करीब एक माह बाद कई देशों में तेल और गैस का व्यापक संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग को बंद किया है, उसके बाद भारत सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। ईंधन की कमी से उपजा वैश्विक संकट अब जिस स्तर पर बढ़ता जा रहा है, उसका भारत पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वह कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर अधिक निर्भर है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचा तो आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक उपायों पर अब व्यापक स्तर पर और गंभीरता से विचार करना होगा। देश में सरकार के समक्ष चुनौती सिर्फ तेल और गैस की कमी की ही नहीं है, बल्कि इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की भी है। मौजूदा संकट का दायरा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपदा में अवसर तलाशने वालों में मुनाफा कमाने की होड़ लग गई है। जमाखोरी कर रसोई गैस सिलेंडर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं, जिससे जरूरतमंद आम लोगों को कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।

ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार की ओर से ऊर्जा के वैकल्पिक उपायों के तौर पर लोगों को घरों में इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक कुकटाप जैसे साधनों का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जा रही है, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम की जा सके। मगर, इन उपायों को अपनाना भी आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बाजार में इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक कुकटाप की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। रसोई गैस की उपलब्धता सामान्य बनाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर हर कदम उठाने के साथ-साथ सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि बाजार में जरूरी वस्तुओं के दामों को नियंत्रण में रखा जाए, नहीं तो संकट कम होने के बजाय और बढ़ेगा।

बाबा साहब आप अवाम के हीरो हैं!

कनक तिवारी

संविधान को लेकर बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के दो तरह के चेहरे दिखाए जाते हैं। संविधान निर्माण के सिलसिले में कुछ लोगों ने बेहूदी टिप्पणियां भी की हैं कि आंबेडकर न तो संविधान निर्माता हैं, न संविधान नियामक और न ही संविधान के अधिकृत प्रवक्ता। उनका तर्क है कि उन्होंने केवल संविधान सभा के सदस्यों और समितियों से मिली तरह-तरह की रिपोर्टों को एकत्रित कर प्रारूप समिति के चेयरमैन की हैसियत से संविधान सभा की बहस के लिए पेश भर कर दिया। बाकी काम तो संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी बहस-मुबाहिसे के जरिए किया। कभी भाजपा में रहे मशहूर पत्रकार अरुण शौरी ने तो 'वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स' (Worshipping False Gods) नाम की किताब भी लिख दी। पता नहीं वह किताब क्यों लिखी गई? उसमें बहुत गलतबयानी है और आंबेडकर के खिलाफ जबरन कई बातें खोजी गई हैं।

दूसरी तरफ, आंबेडकर के पक्ष में जातीय समरसता की चाह रखने वाले तथा अन्य प्रताड़ित लोग उनकी देवता की तरह पूजा करते हैं। वे संविधान निर्माण के संदर्भ में आंबेडकर की भूमिका को आलोचनात्मक आधार पर सुनना-समझना नहीं चाहते। उनका यहां तक कहना होता है कि संविधान केवल बाबा साहब की अकेली और मौलिक देन है। बाकी संविधान निर्माताओं के संबंध में उनकी कोई सार्थक टिप्पणी नहीं होती। वे बाबा साहब के जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस की बड़ी बहसों में ऐसे लोगों को नहीं बुलाते जो उनकी निगाह में सवर्ण हैं और जिन्हें वे बाबा साहब का मूल्यांकन करने में पैदाइशी असमर्थ मानते हैं। यह भी आंबेडकर पर एक तरह की एकाधिकारवादिता है। इससे आंबेडकर का यश लोकजीवन में विस्तारित कैसे होगा? ऐसे लोग उन बारीकियों को भी नहीं खोजते जो बाबा साहब की वास्तविक विशेषताएं हैं।

आंबेडकर को लेकर एक बात बहुत साफ है—उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर कोई अहसान नहीं किया गया। वे आजादी की लड़ाई के योद्धा या किसी विशिष्ट पार्टी के (पारंपरिक) सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी बौद्धिक प्रतिभा का कोई सानी नहीं था। इसलिए आंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि इतिहास की अनिवार्यता थी। मैं विनम्र जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यदि बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं होते, तो संविधान उस तरह लगभग 300 सदस्यों की बहस को अपनी प्रतिभा से समेटते हुए तीन वर्षों में लिखा नहीं जा सकता था। इतिहास का सच यह है कि आंबेडकर का कोई विकल्प नहीं था। संविधान के एक-एक अनुच्छेद पर बाबा साहब की तीखी नजर रहती थी। वे न तो कभी गफलत में रहते थे और न ही किसी बिंदु की अनदेखी करते थे। यह जानना भी जरूरी है कि उनके साथ सहयोग करने के लिए कानूनी विद्वानों की एक विशेषज्ञ समिति भी थी, जो उनके साथ सहकार्य करती थी। इसका आभार स्वयं बाबा साहब ने भी माना है। अक्सर आंबेडकर की सबसे बड़ी खूबी का ब्यौरा लोग देते ही नहीं। वे स्वयं कई तरह की संवैधानिक व्याख्याओं में विश्वास करते थे, जिसका विवरण उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में दिया है। जब संविधान सभा का बहुमत उनसे सहमत नहीं होता था (चाहे उसकी कोई भी वजह रही हो), तब यह आंबेडकर की उदारता थी कि उन्होंने निजी रूप में व्यक्त अपने विचारों को प्रारूप समिति के चेयरमैन के कर्तव्यों के नीचे दबा दिया। यदि आंबेडकर की उन निजी रायों को बहुमत ने खारिज कर 'दाखिल दफ्तर' न किया होता, तो शायद आज हिंदुस्तान के आईन (संविधान) की हालत और बेहतर होती।

मसलन, जब मूल अधिकारों को लेकर सरकार पर बंदिश लगनी थी कि मूल अधिकार तभी प्रभावित होंगे जब वे 'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' (Due Process of Law) की परीक्षा में खरे उतरें। तब संविधान सलाहकार बी.एन. राव ने सुझाव दिया कि अमेरिका के सबसे प्रभावशाली जज फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने सलाह दी है कि यदि जनता के मूल अधिकारों की जांच अदालतें 'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' के तहत करेंगी, तो मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। भारत, अमेरिका की तरह पुराना अनुभवसिद्ध लोकतंत्र नहीं है। तब एक नया लोकतंत्र शासन कैसे करेगा? इसलिए इसे 'प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ' (Procedure Established by Law) किया गया। बहुत दुख के साथ आंबेडकर ने तब कहा था— "मैं मानता हूं कि ऐसा मंत्रिमंडल आ सकता है जो जनता के खिलाफ अनुचित फैसला करे, और दूसरी ओर काले कोट में सजे पांच-छह जज बंद कमरे में बैठकर सरकारी फैसला बदल दें। यह एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है।" मंत्रिपरिषद और सुप्रीम कोर्ट के संभावित विवाद को लेकर उन्होंने कहा था कि आप लोग स्वयं फैसला करिए, मैं कुछ नहीं कह सकता।

हिंदू-मुस्लिम के सवाल पर आंबेडकर दूसरों से ज्यादा वैज्ञानिक और स्पष्टवादी थे। उन्होंने साफ कहा था कि यदि बहुसंख्यक यह सोचें कि अल्पसंख्यक उन पर बोझ हैं या इतिहास की कोई दुर्घटना हैं, तो अल्पसंख्यक भयंकर विस्फोटक के समान हो जाते हैं। अगर वे फटे, तो सारे राजकीय ढांचे को तहस-नहस कर सकते हैं; यूरोप का इतिहास इसका उदाहरण है। यह नजरिया बदलना पड़ेगा। साथ ही अल्पसंख्यकों को भी यह सोचना होगा कि वे हर समय पूरी तरह सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर अलग-थलग ही रहेंगे, तो वह भी एक गलत नजरिया है। आज यक्ष प्रश्न यह है कि बाबा साहब ने तो देशवासियों को बहुत कुछ दिया, लेकिन बाद की भारतीय पीढ़ियों ने उनकी कितनी बातें मानीं? दलितों के मसीहा ने अधिकारों के लिए भीख नहीं मांगी, बल्कि संघर्ष करना सिखाया। आज उनके नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान सजाने वाले अनुयायी दलित वर्गों को कई हिस्सों में बांट चुके हैं। दलित महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार की खबरें आज भी आती हैं। योग्यता के बावजूद उन्हें उच्च पदों पर स्थान पाने में संघर्ष करना पड़ता है। न्यायपालिका में उनकी स्थिति क्या है? क्या वाकई जातिवाद खत्म हो रहा है? क्या जातीय जनगणना ही उनके उत्थान का इकलौता रास्ता है?

नागपुर में बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। आंबेडकर की शोहरत 'उपलों की दीवार' नहीं है जिसे एक झटके में गिरा दिया जाए। उन्होंने सिखाया कि संविधान वह किताब है जो हर हिंदुस्तानी के हाथ में होनी चाहिए। आज देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र और सरकार चल रही है। तो फिर संविधान की पोथी हर हाथ में क्यों नहीं हो सकती? ताकि हर मनुष्य के भीतर अपनी जम्हूरियत (लोकतंत्र) का गौरव जागृत हो सके।

जंग लंबी चली तो बदल जाएगा दुनिया का भविष्य

विवेक शुक्ला

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत इन दिनों पूरी दुनिया की नजरों में है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से हो रही यह वार्ता खाड़ी युद्ध को खत्म करने का आखिरी मौका प्रतीत हो रही है। फरवरी 2026 में शुरू हुए इस संघर्ष ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित कर दिया है, हजारों लोगों की जान ले ली है और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। दो हफ्ते का सीजफायर फिलहाल टिका हुआ है, लेकिन अगर इस्लामाबाद में बातचीत नाकाम रही और जंग लंबी खिंची, तो जिंदगी बुरी तरह हिल जाएगी।

सबसे बड़ा झटका ऊर्जा बाजार को लगेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20-25 प्रतिशत तेल गुजरता है। अगर ईरान ने फिर से इसे ब्लॉक किया या हमले बढ़ाए, तो रोजाना 15-20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई रुक सकती है। अभी तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी हैं। लंबी लड़ाई की स्थिति में ये 130 से 170 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे अब तक का सबसे गंभीर 'सप्लाई शॉक' बताया है। गैस की कीमतें भी दोगुनी हो जाएंगी। नतीजा साफ है—हर जगह महंगाई का कहर। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और खाने-पीने की चीजें, सब कुछ महंगा हो जाएगा। विकसित देशों में मंदी की आशंका बढ़ जाएगी, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत, चीन और दक्षिण कोरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी क्योंकि ये तेल के बड़े आयातक हैं।

ग्लोबल इकोनॉमी पर असर और भी गहरा होगा। अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अगर युद्ध कुछ महीनों तक चला तो दुनिया की जीडीपी 0.2 से 1.2 प्रतिशत तक गिर सकती है। शेयर बाजारों में भारी उथल-पुथल मचेगी, सप्लाई चेन बाधित होगी और यूरोप तथा एशिया में गैस संकट और गहरा जाएगा। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह चोट खाएगी। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत में बुनियादी ढांचे पर हमले हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार, अरब देशों की जीडीपी पर 120 से 194 बिलियन डॉलर का भारी असर पड़ सकता है। मानवीय संकट भी विकराल रूप ले लेगा। अभी तक हजारों मौतें हो चुकी

हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। शरणार्थी संकट यूरोप और एशिया तक फैल सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चरमरा जाएंगी। इसके साथ ही पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि युद्ध में तेल सुविधाओं और रिफाइनरियों पर हमले से प्रदूषण बढ़ेगा। वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अमेरिका-ईरान जंग से रूस और चीन को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। रूस, यूक्रेन मोर्चे पर अपना ध्यान बंटा सकेगा, जबकि चीन सस्ते दामों पर तेल खरीदकर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करेगा। खाड़ी देश अमेरिका पर अपना भरोसा खो सकते हैं। नाटो गठबंधन में दरारें और गहरी होंगी। मध्य पूर्व में नए गठजोड़ बन सकते हैं। इजराइल-लेबनान फ्रंट एक बार फिर गर्म हो सकता है जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी।

भारत पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ेगा। हमारा लगभग 40 प्रतिशत तेल और 80 प्रतिशत गैस मध्य पूर्व से आता है। तेल की कीमतें चढ़ने से आयात बिल आसमान छू जाएगा, रुपया और कमजोर होगा तथा मुद्रास्फीति पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय मजदूर पहले ही वापस लौट रहे हैं। लंबी जंग का मतलब सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा होगा। उर्वरक महंगे होने से फसलें प्रभावित होंगी, जिससे खाद्यान्न की कीमतें बढ़ेंगी। गरीब देशों में भुखमरी बढ़ेगी और विकासशील दुनिया में आर्थिक अस्थिरता फैल जाएगी।

साप्ताहिक शहर सत्ता

महिला आरक्षण बिल: बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप

3 दिन सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अपने सभी सांसदों के लिए तीन-लाइन का व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

पार्टी के निर्देश के अनुसार सभी सांसदों, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, सभी को तीन दिनों की इस बैठक के दौरान सदन में लगातार उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। व्हिप में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपस्थिति अनिवार्य है और इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की छुट्टी (अवकाश) स्वीकृत नहीं की जाएगी। बीजेपी ने पत्र में कहा है, 'लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के सभी सदस्यों के लिए गुरुवार से शनिवार, यानी 16 से 18 अप्रैल 2026 तक के लिए तीन-लाइन का व्हिप जारी किया जा रहा है। सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों और सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त तीनों तिथियों के दौरान सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।' पत्र में आगे लिखा है, 'सदन में उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी सदस्य को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस व्हिप का कड़ाई से पालन करें और सदन में अपनी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करें। आपके सहयोग की हम सराहना करते हैं।'

महिला आरक्षण बिल को लेकर व्हिप जारी

संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र को लेकर बीजेपी ने सांसदों को निर्देश दिया है। इस सत्र का मुख्य केंद्र 'महिला आरक्षण संशोधन विधेयक' होगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण संशोधनों पर सरकार विचार कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' में महिलाओं के लिए आरक्षण को अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया था। हालांकि, जनगणना में हो रही देरी के चलते अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आगे बढ़ने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

पीएम ने महिला आरक्षण संशोधन बिल पर कांग्रेस से मांगा समर्थन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों को एक चिट्ठी लिखकर महिला आरक्षण बिल में संशोधन पास करवाने के लिए समर्थन मांगा है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सरकार बिना कानून के बारे में कोई जानकारी दिए विपक्ष से सहयोग मांग रही है। खरगे ने कहा कि इससे विपक्ष का यह यकीन और पक्का हो जाता है कि केंद्र सरकार इस बिल को लागू करने में इसलिए जल्दबाजी कर रही है ताकि वह महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के बजाय राजनीतिक फायदा उठा सके। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि16 अप्रैल से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी एक ऐतिहासिक चर्चा होने वाली है। यह विशेष सत्र हमारे लोकतंत्र को और मज़बूत करने का एक अवसर है। यह एक ऐसा पल भी है जब हम सबको साथ लेकर, मिलकर आगे बढ़ने की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहरा सकते हैं। मैं इसी भावना और उद्देश्य के साथ आपको यह चिट्ठी लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि काफी सोच-विचार के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब समय आ गया है कि पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उसकी सही भावना के साथ लागू किया जाए। यह बहुत जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ ही कराए जाएं। इससे भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और जनता का भरोसा मजबूत होगा। इससे शासन-प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। सांसदों से इस संशोधन का समर्थन करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा होगा अगर संसद के कई सदस्य इस विषय पर संसद में अपने विचार व्यक्त करें। यह किसी एक पार्टी या व्यक्ति से ऊपर का क्षण है।

बंगाल चुनाव से पहले ED का बड़ा एक्शन! कोयला से हवाला तक बड़े नाम रडार पर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ED ने एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध वसूली, जमीन कब्जा, भर्ती घोटाले और अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है. बीते कुछ दिनों में राज्य के अलग-अलग मामलों में छापेमारी, संपत्ति अटैचमेंट, समन जारी करने और चार्जशीट दाखिल करने जैसी कई बड़ी कार्रवाई सामने आई हैं. इन कार्रवाइयों में राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों, कारोबारियों और कथित अपराध सिंडिकेट से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं.

सबसे पहले बात करते हैं IPAC केस की. 2 अप्रैल 2026 को ED ने देश के कई शहरों हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा और रांची में एक साथ 11 ठिकानों पर छापेमारी की. ये छापे IPAC के दफ्तरों, उसके डायरेक्टर्स के घरों और उससे जुड़ी कंपनियों के ऑफिस पर मारे गए. जांच के दौरान ED को ऐसे दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और घरेलू ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं. जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि चुनावी गतिविधियों के नाम पर कहीं अवैध फंडिंग तो नहीं हो रही थी.इस केस में छापेमारी के दौरान खुद राज्य की सीएम ममता बनर्जी जबरन दस्तावेज लेकर चली गई थीं.सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर उन्हें फटकार लगाई थी

पार्थ चटर्जी केस में ED की दबिश तेज

पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी एक बार फिर ED के निशाने पर हैं. 11 अप्रैल 2026 को कोलकाता में उनके आवास और सहयोगी प्रसन्न कुमार रॉय के दफ्तर पर छापेमारी की गई. ED के मुताबिक, SSC भर्ती घोटाले में उन्हें तीन बार समन भेजा गया लेकिन वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए.गौरतलब है कि 2022 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था और 2025 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिली थी. अब ED उनके खिलाफ प्राथमिक शिक्षक, SSC असिस्टेंट टीचर और ग्रुप C-D भर्ती से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है.

इस्लामाबाद में फेल हुई अमेरिका के साथ शांति वार्ता

नई दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अहम बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई. 21 घंटे तक चली बातचीत के बेनतीजा होने पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी. ईरान ने कहा कि अमेरिका हमारा भरोसा जीतने में फेल हो गया. हालांकि, तेहरान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने की कोशिश के लिए पाकिस्तान से शुक्रिया कहा है.इस्लामाबाद वार्ता में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने कहा कि ईरान ने इस शांति वार्ता में पूरी नीयत के साथ बातचीत की और अपने देश के हितों को सामने रखा, लेकिन पिछले अनुभवों के कारण हम अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'बातचीत से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास जरूरी सद्भावना और इच्छाशक्ति है, लेकिन पिछले दो युद्धों के अनुभव के कारण हमें सामने वाले पक्ष पर यकीन नहीं है.'वार्ता के फेल होने के बाद ईरान ने साफ कहा था कि इस बातचीत के रुकने का सबसे बड़ा कारण अमेरिका की ओर से रखी गई बेबुनियाद और अनुचित मांग रहीं. हमारी टीम ने करीब 21 घंटे तक लगातारबातचीत की।

अमेरिका ने क्या रखी थी शर्त?

इस्लामाबाद की मेजबानी में हुई बातचीत के दौरान अमेरिका ने कुछ ऐसी शर्तें ईरान के सामने रखीं, जो ईरान के लिए मानना बेहद मुश्किल था. इस शर्तों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी स्थिति और परमाणु सामग्री को हटाने जैसे मुद्दे शामिल थे. होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इस महत्वपूर्ण रास्ते से होकर आगे बढ़ता है.

अगले हफ्ते तक 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान

आसमान से बरसेगी आग! कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप अप्रैल महीने से ही दिखने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अनुमान है कि अगले हफ्ते बुधवार (15 अप्रैल, 2026) तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीटवेव का भी अलर्ट जारी किया है. IMD ने कहा कि दिल्ली में हाल ही में हुई हल्की बारिश के बाद तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी देखी गई है. शनिवार (11 अप्रैल, 2026) को भी शहर में दिन भर तेज धूप खिली रही और अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि, यह तापमान अभी सामान्य से 1.4 डिग्री कम है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. IMD ने कहा कि शुक्रवार (17 अप्रैल) तक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है.

पिछले हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली में अप्रैल का दशक का सबसे कम अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इसके बाद से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो गर्मी के मौसम की शुरुआत का संकेत है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान में 6–7 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, जिससे यह सामान्य से नीचे से बढ़कर सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा. वहीं, न्यूनतम तापमान, जो फिलहाल 18.6 डिग्री सेल्सियस है और औसत से कम है, उसमें भी धीरे-धीरे वृद्धि होने की उम्मीद है. गुरुवार (16 अप्रैल) तक यह 23-25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं

एक्सपर्ट्स का मानना है कि तापमान में यह बढ़ोतरी साफ आसमान और मौसम में किसी भी तरह की बाधा न होने के कारण हो रही है. स्काइमेट वेदर के महेश पलावत ने कहा, 'आने वाले दिनों में शुष्क हवाएं चलेंगी, क्योंकि उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर कम हो रहा है. लगातार तेज धूप, बिना बादलों और बिना बारिश के कारण तापमान बढ़ना तय है.' उन्होंने कहा कि अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाकर सामान्य से काफी ज्यादा हो जाता है, तो हीटवेव जैसी भी स्थिति बन सकती है.

इजरायली हमलों में लेबनान के 18 लोगों की मौत

नई दिल्ली। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं. लेबनान के अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच शुरू हुए युद्ध में मरने वालों की कुल संख्या 2,000 से अधिक हो गई है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि दक्षिणी लेबनान के सिडोन के पास एक गांव पर इजरायली हमलों में कम से कम 8 लोग मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए. इससे पहले बताया था कि नबातीह जिले में इजरायली हमलों में 3 आपातकालीन कर्मचारियों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए थे. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 मार्च को लेबनान के ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध में शामिल होने के बाद से कम से कम 2,020 लोग मारे गए हैं और 6,436 अन्य घायल हुए हैं. हिज़्बुल्लाह ने ईरान के समर्थन में इजरायल पर रॉकेट दागे, जिससे इजरायल ने बड़े पैमाने पर हमले किए और जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई की।

गिल-बटलर के अर्धशतक, गुजरात ने लखनऊ को 7 विकेट से हराया

अहमदाबाद। गुजरात ने लखनऊ को उनके होम ग्राउंड पर कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर की अर्धशतकीय पारी के दम पर आसानी से 7 विकेट से हरा दिया। गुजरात को इस जीत की बेहद जरूरत थी जो इस टीम ने हासिल किया और अंकतालिका में अपनी स्थिति भी मजबूत की। चौथे मैच में ये गुजरात की दूसरी जीत रही तो वहीं पंत की टीम को चौथे मैच में दूसरी हार मिली। लखनऊ के खिलाफ 4 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटंस (GT) की भिड़ंत लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। इस मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 164 रन बनाए। गुजरात ने दूसरी पारी में 18.4 ओवर में 3 विकेट पर 165 रन बनाकर मैच जीत लिया। गुजरात और लखनऊ की टीम ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। लखनऊ के ओपरन मार्करम ने 30 रन बनाए जबकि मिचेल मार्श 11 रन के स्कोर पर निपट गए। तीसरे नंबर पर आए कप्तान पंत ने 18 रन की पारी खेली जबकि आयुष बदोनी ने 9 रन की पारी खेली। निकोलस पूरन ने 19 रन जबकि अब्दुल समद और मुकुल चौधरी ने 18-18 रन की पारी खेली। जॉर्ड लिंडे ने 16 रन बनाए जबकि मोहम्मद शमी ने नाबाद 12 रन बनाए जबकि आवेश खान ने नाबाद 4 रन की पारी खेली। प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए जबकि अशोक शर्मा ने 2 जबकि मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा ने एक-एक विकेट लिए। लखनऊ के खिलाफ गिल ने 34 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और 56 रन की पारी खेली। साई सुदर्शन ने इस मैच में 15 रन की पारी खेली। वहीं बटलर ने 29 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और वो 60 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 13 गेंदों पर नाबाद 21 रन जबकि राहुल तेवतिया ने 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिला दी। लखनऊ की तरफ से प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी और आवेश खान को एक-एक विकेट मिले। शमी को इस मैच में भी खाली हाथ रहना पड़ा और उन्हें 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं मिला।

लगातार 3 हार के बाद पथिराना की वापसी से मजबूत होगी केकेआर

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के IPL 2026 में चार लीग मैच हो चुके हैं. टीम को तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा. अब लगातार तीन हार झेलने के बाद केकेआर को बड़ी मजबूती मिलने वाली है, जो मथिशा पथिराना के रूप में होगा. पथिराना कोलकाता के लिए खेलने के लिए तैयार है. क्रिकबज के मुताबिक, इंजरी से जूझ रहे पथिरान को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC मिल गई है. बता दें कि फ्रेंचाइजी ने पथिराना को 2026 सीजन के लिए 18 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था.

अगले मैच से होगे उपलब्ध

रिपोर्ट में बताया गया कि पथिराना कोलकाता के लिए अगले मैच से ही उपलब्ध हो जाएंगे. कोलकाता का अगला यानी पांचवां लीग मैच 14 अप्रैल, मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. देखना दिलचस्प होगा कि शुरुआती चार मैचों तक बाहर रहने वाले पथिराना टीम को कितना फायदा पहुंचाते हैं. पथिराना के अलावा फ्रेंचाइजी और भी तेज गेंदबाजों की कमी से जूझ रही है. टीम के मुख्य तेज गेंदबाजों में शामिल हर्षित राणा पहले से ही बाहर हैं. इसके अलावा आकाश दीप भी नहीं खेल रहे हैं. गौर करने वाली बात यह है कि कोलकाता ने पथिराना का कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा, बल्कि फ्रेंचाइजी गेंदबाज की प्रतगि के लिए लगातार श्रीलंका बोर्ड के साथ संपर्क में रही.

वर्ल्ड कप में चोटिल थे पथिराना

पथिराना को 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चोट लगी थी, जिसके चलते वह क्रिकेट से दूर थे. अब वह वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं. आईपीएल के मौजूद सीजन में उनकी वापसी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हो सकती है, जिसका पहले पथिराना हिस्सा थे. पथिराना ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 32 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 32 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 21.61 की औसत से 47 विकेट चटकाए, जिसमें बेस्ट फिगर 4/28 का रहा.

भारत में महिलाओं ने लिया 76 लाख करोड़ का कर्ज

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में महिलाएं भी जोर कदम से अपना योगदान दे रही हैं. घर की चारदीवारी से निकलकर महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. यहां तक की बिजनेस की दुनिया में भी नए-नए मुकाम हासिल कर रही हैं. नीति आयोग की रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही कह रही है. NITI Aayog की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला कर्जदारों के पास कुल 76 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट पोर्टफोलियो है. यह 2025 तक कुल सिस्टम क्रेडिट का 26 परसेंट है और 2017 के बाद से इसमें 4.8 गुना की बढ़ोतरी हुई है.'From Borrowers to Builders: Women and India's Evolving Credit Market' (उधारकर्ताओं से निर्माताओं तक: महिलाएं और भारत का उभरता क्रेडिट बाजार) शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2025 के बीच क्रेडिट लेने वाली सक्रिय महिला उधारकर्ताओं की संख्या 9 परसेंट CAGR से बढ़ी है।

कितनी है वैभव की असली उम्र ?

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाजों पर भी कहर बनकर टूट रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान तो कह चुके हैं कि वैभव के नाम से बड़े-बड़े गेंदबाज भी डरे हुए हैं. IPL 2026 में अब तक 15 वर्षीय वैभव ने 200 रन बना लिए हैं. खूब सारे रन बनाने तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह उन्होंने जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गजों को निशाना बनाया है वह अविश्वसनीय है.वैभव ने पिछले सीजन भी तबाही मचाई हुई थी, जहां उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 7 मैचों में 252 रन बनाए थे, वो भी 206 से अधिक के स्ट्राइक रेट से. तभी से उनकी उम्र पर सवाल उठते रहे हैं. सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल उठाते रहे हैं कि वैभव ने उम्र में हेराफेरी की है. मगर इन आरोपों के बीच एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें BCCI द्वारा वैभव का बोन टेस्ट करवाने का दावा किया गया है. IPL 2025 सीजन के समय जब वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर सवाल उठे थे, तब वैभव के पिता संजीव ने खुलासा किया था कि 2019 में BCCI ने उनके बेटे का बोन टेस्ट करवाया था और उस बोन टेस्ट से सब साफ हो गया था कि वैभव ने उम्र में कोई हेराफेरी नहीं की है. अब उसी बोन टेस्ट के संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है.वायरल पोस्ट में एक व्यक्ति ने दावा किया है कि BCCI ने 2019-20 सत्र के समय वैभव का बोन टेस्ट किया था, उन दिनों वैभव अंडर-16 खेल रहे थे. इस पोस्ट में बताया गया कि उस समय वैभव की उम्र लगभग 8.5 वर्ष थी, लेकिन 2 अलग-अलग बार बोन टेस्ट करने पर उनकी उम्र 10.4 साल और 10.1 आई थी. इसमें 2 साल से कम का अंतर है, जो स्वीकृत सीमा के अंदर बताया गया।

भारी कर्ज और वित्तीय संकट, क्या डूब जाएगी स्पाइसजेट

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक स्पाइसजेट फिलहाल बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही है. जिसके चलते कंपनी ने अपने साथ काम कर रहे स्टाफ को कम करने का फैसला किया है. कंपनी ने इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए अपने स्टाफ में से 20 प्रतिशत को कम करने का मन बना लिया है. खबरों की मानें तो कंपनी जल्दी ही अपने कई कर्मचारियों को बिना वेतन दिए अस्थाई रूप से अवकाश पर भेजने वाली है. फिलहाल कंपनी में 6,800 कर्मचारी हैं, इन्हीं में से कई छटनी में बाहर कर दिए जाएंगे. तो वहीं कंपनी के पास अपने केवल 13 ही प्लेन बाकी रह गए हैं, जिनमें 10 बोइंग विमान हैं और 3 Q400 शामिल हैं. इसके अलावा 14 प्लेन लीज पर भी चल रहे हैं. अपनी वित्तीय परेशानियों के बीच कंपनी ने अन्य सीनियर कर्मचारियों की 2-3 महीने की सैलेरी भी नहीं दी है. TDS और PF की 100 करोड़ से भी ज्यादा की राशि बाकी है।

डग आउट में फोन यूज कर फंसे राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रही राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर का डगआउट में बैठकर मोबाइल चलाना उन्हें मुश्किल में डालता हुआ नजर आ रहा है. मैच के बीच इस तरह डगआउट में मोबाइल का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ होता है. अब इस मामले पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बात करते हुए बताया कि टीम के मैनेजर पर कार्रवाई होनी चाहिए. बता दें कि रोमी भिंडर का डगआउट में मोबाइल चलाना आईपीएल के प्लेयर्स एंड मैच ऑफीशियल्स एरिया (PMOA) प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. राजस्थान ने चौथा मैच 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गुवाहाटी में खेला था. इसी मैच के दौरान डगाउट में मोबाइल चलाने वाला वीडियो सामने आया. बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "रोमी भिंडर ने वाकई में PMOA प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है।

हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बना नया सुपर पैनल

अब कम होंगे अस्पताल के भारी-भरकम बिल

नई दिल्ली। अस्पताल के भारी-भरकम बिल को चुकाना हर किसी के लिए मुसीबत की तरह होता है. यहां तक कि यदि किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है तो उसमें भी काफी समय लग ही जाता है. इसी स्थिति को देखते हुए और प्रोसेस में पारदर्शिता के मकसद से IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक नया नियम लागू करने के बारे में सोचा है. जिससे क्लेम की प्रक्रिया आसान होगी साथ ही साथ हॉस्पिटल अपना मनमानी बिल नहीं वसूल पाएंगे. इसके लिए एक नई उप कमेटी का गठन किया गया है.

नई कमेटी का गठन

IRDAI ने अस्पतालों के मनमानी बिल पर रोक लगाने के लिए नई उप कमेटी का गठन किया है. ये उप कमेटी हेल्थ इंश्योरेंज के जरिए इनोवेशन, वाइडर कवरेज, बेहतर रिस्क और बेहतर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए रेग्युलेटरी, पॉलिसी और ऑपरेशनल मेजर्स को रेकमंड करेगी. इस कमेटी के गठन का मकसद उपभोक्ताओं के लिए प्रोसेस में पारदर्शिता लाना और पॉलिसीधारकों के लिए इंश्योरेंस को ज्यादा आसान बनाना है.

IRDAI का मकसद?

इस कमेटी के गठन के साथ ही इरडा का नए नियमों के साथ मकसद साफ है. उन्हें लोगों के लिए क्लेम एक्सपीरियंस को सुगम बनाना है. हॉस्पिटल के टैरिफ में सुधार करना है, जिससे वो मनमानी फीस मरीजों से ना वसूल पाएं. इससे डिजिटल सिस्टम भी दुरुस्त होगा. लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी. इसके अलावा पूरी प्रोसेस पारदर्शिता के साथ होगी, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा. प्रोबस के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश गोयल का इसे लेकर कहना है कि, 'फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस होने की वजह से उनसे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं. नई कमेटी का सबसे पहला काम इन टैरिफ और अस्पतालों के नेटवर्क की विसंगतियों को दुरुस्त करना है. इसका सीधा फायदा ये होगा कि इलाज की कीमतें सही होंगी और बिलिंग भी एक जौसी ही होगी.

साप्ताहिक शहर सत्ता

19 बदले नामों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश

पिछली सूची को पीसीसी ने किया था निरस्त,बिना मंजूरी जारी लिस्ट को बताया था अमान्य

शहर सत्ता/रायपुर। नई सूची में 19 नामों में बदलाव के बाद संगठन ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। आधिकारिक अनुमोदन मिलने के बाद अब इस विवाद पर विराम लगने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर वार्ड अध्यक्षों की सूची को लेकर कांग्रेस संगठन के भीतर चल रहे विवाद के बाद नई संशोधित सूची जारी कर दी गई है। इस नई सूची में 19 नामों में बदलाव किया गया है, जिसे अब आधिकारिक मंजूरी भी मिल गई है। कांग्रेस के संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने आदेश जारी कर सभी नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रायपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्तियों को भी हरी झंडी मिल गई है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सभी जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी 15 अप्रैल तक गठित करने के निर्देश दिए थे। इसी दौरान रायपुर शहर कांग्रेस ने 66 वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी कर दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर पीसीसी ने इस सूची को निरस्त कर दिया था। पीसीसी की ओर से स्पष्ट किया गया था कि वार्ड अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की सूची जारी करने से पहले आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए इसे अवैधानिक माना गया। दरअसल, इससे पहले हुई समीक्षा बैठक में कार्यकारिणी और वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति में देरी को लेकर नाराजगी जताई गई थी। इसी के बाद शहर कांग्रेस ने जल्दबाजी में सूची जारी कर दी थी। हालांकि, सूची जारी होते ही इस पर आपत्ति दर्ज की गई और पीसीसी ने तत्काल प्रभाव से उसे खारिज कर दिया था, जिससे संगठन के भीतर विवाद और गहरा गया था।

अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा कब पूरा करेगी भाजपाः बैज

रायपुर। दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव मे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा भाजपा ने किया था लेकिन अब वह अपने वादे को भूल गयी है।भाजपा सरकार की वादाखिलाफी उच्च न्यायालय में एक बार फिर उजागर हुई है।

100 दिन के भीतर नियमितीकरण का वादा था सवा दो साल बीत जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी ठगे जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में सुनवाई के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकारी संवैधानिक नियोक्ता है और गरीब कर्मचारियों के दम पर अपना बजट संतुलित नहीं कर सकती। जो लोग बुनियादी और महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को संभाल रहे हैं उनके हित में सहानुभूति पूर्वक विचार कर चार महीने के भीतर निर्णय लेने के कठोर निर्देश जारी किया गया है। भाजपा सरकार की नीयत नहीं है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और इसीलिए आउटसोर्सिंग के जरिए काम लेकर नियमित नियुक्तियों से बचने का कुत्सित प्रयास भाजपा की सरकार हर विभाग में कर रही है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र में क्रांतिकारी कदम : सरोज

रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। बहुत से दल इससे पहले भी यह विधेयक लेकर आए। कभी किसी ने एक सदन में पारित किया तो दूसरे सदन में उसको रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। देश की आधी आबादी को उनका अधिकार प्रधानमंत्री ने दिया है। सबके विकास में महिलाओं को भी जोड़ा।

यह बात भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने शनिवार को पत्रवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर नारीत्व को सम्मान देने के लिए देश की सभी बहनें प्रधानमंत्री को साधुवाद देती हैं। उन्होंने इतनी ताकत के साथ भारत की संसद में इस अधिनियम को रखा तब परिस्थितियां सकारात्मक नहीं थीं। प्रधानमंत्री ने 2029 में यह बिल लागू करने की दिशा में कार्य किया, अभी उस पर संशोधन आ रहा है। आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में संशोधन के साथ 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ यह बिल पारित होगा। आज महिलाएं नीति-निर्धारक भी हैं, केवल नीति के लाभार्थी नहीं हैं।

महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम : राजवाड़े

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मुताबिक ये बिल महिलाओं के जीवन में बदलाव लाएगा। दीनदयाल ऑडिटोरियम में 15 अप्रैल को कार्यक्रम होगा। 11 से 16 अप्रैल तक संभाग स्तर पर नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें सामाजिक संगठनों, महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की सक्रिय भूमिका होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री साय, प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ कार्यसमिति सदस्य और सभी पदाधिकारी रहेंगे

बंगाल चुनाव के बाद कार्यसमिति से पहले परिचय के लिए होगी प्रदेश भाजपा संगठन की बड़ी बैठक

रायपुर। प्रदेश भाजपा संगठन की प्रदेश कार्यसमिति करीब डेढ़ साल से नहीं हो सकी है। इसके अभी और लंबे समय तक होने की संभावना नहीं है। इधर कार्यसमिति के सदस्यों का भी ऐलान हो गया है। अब कार्यसमिति से पहले प्रदेश भाजपा संगठन कार्यकारिणी के सदस्यों के परिचय के लिए एक बड़ी बैठक बंगाल चुनाव के बाद इस माह के अंत में या मई के पहले सप्ताह में करने की तैयारी में है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी मंत्री, कई विधायक और सांसदों के साथ ही प्रदेश के संगठन के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी आ सकते हैं। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल तो रहेंगे ही।

किरण देव को पूर्णकालिक अध्यक्ष बने एक साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक एक भी कार्यसमिति नहीं हो सकी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रीय कार्यसमिति के बाद ही आमतौर पर प्रदेश कार्यसमिति होती है। करीब डेढ़ साल से राष्ट्रीय कार्यसमिति भी नहीं हो सकी है। अब नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनकी कार्यकारिणी के बनने के बाद जब राष्ट्रीय कार्यसमिति होगी तब जाकर प्रदेश की कार्यसमिति होगी। इसके पहले कार्यसमिति के सदस्य छह माह लंबे इंतजार के बाद अब जाकर तय हुए हैं। लेकिन प्रदेश की कार्यसमिति के लिए अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

डेढ़ साल से नहीं हुई है कार्यसमिति

प्रदेश कार्यसमिति हर तीन माह में करने का प्रावधान तो है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम यह है कि राष्ट्रीय कार्यसमिति के बाद ही प्रदेश कार्यसमिति होती है। राष्ट्रीय कार्यसमिति में जो तीन माह की कार्ययोजना तय होती है, उसी पर प्रदेश कार्यसमिति में चर्चा होती है। इसके बाद जिलों और फिर मंडल में कार्यसमिति होती है। छत्तीसगढ़ में सितंबर 2024 में भाजपा के सदस्य अभियान से पहले प्रदेश कार्यसमिति हुई थी, इसके बाद से करीब डेढ़ साल से कार्यसमिति नहीं हुई है।

उर्वरको के बारे मे सरकार की चुप्पी किसानों की चिंता का कारण ?

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन आने वाला है। सरकार ने अभी तक उर्वरकों की व्यवस्था के बारे में निश्चिंत बनी हुई है। उर्वरको के बारे मे सरकार की चुप्पी किसानों की चिंता का कारण बनी हुई है। अभी तक सरकार को किसानों की जरूरत के अनुसार सोसायटियों से मांग का डाटा एकत्रित कर सभी सोसायटियों में खाद पहुंचाना शुरू कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार बताये कि इस वर्ष कितने उर्वरकों की जरूरत का आंकलन किया गया तथा सरकार के पास कितनी उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है? प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन में राज्य के किसानों को 14 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता थी, साय सरकार शुरू के दो माह तक मात्र 80 हजार मीट्रिक टन ही उर्वरक दे पायी थी, आखिर तक जरूरत से आधे का भी इंतजाम नहीं कर पायी सरकार। किसान यूरिया से लेकर डीएपी और पोटाश सभी के लिए भटकते रहे, बिचौलियों के द्वारा ब्लेक मार्केट में तीन से चार गुने दाम में किसानों को यूरिया और डीएपी खरीदने को मजबूर होना पड़ा था। आगामी खरीफ सीजन में 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता अनुमानित है, पर इस सरकार की तैयारी आधी भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि किसान खरीफ सीजन शुरू होने के तीन महिना पहले फरवरी में ही अपनी डिमांड सोसायटी के माध्यम से सरकार तक पहुंचा देते है।

बिजली बिल सरकार प्रायोजित लूट साबित हो रही - कांग्रेस

रायपुर। बढ़े बिजली बिल ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बिजली बिल सरकार प्रायोजित लूट साबित हो रहा है।चार महिने से आ रहे बेतहाशा बढ़ा बिजली बिल से राज्य का हर नागरिक परेशान है। 200 यूनिट हाफ बिजली योजना से भी कोई राहत नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार भूपेश सरकार के समय शुरू की गयी बिजली बिल हाफ योजना को फिर शुरू करें, ताकि जनता को बढ़े बिजली बिल में कुछ राहत मिल सके। बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के कारण जनता बिजली के बिल नहीं पटा पा रही उनकी लाईन काटी जा रही। प्रदेश में हजारो उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि सरकार की नाकामी लापरवाही और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण प्रदेश के लोगों के लिए बिजली कटौती और मंहगी बिजली बड़ी समस्या बन गई है। राज्य बनने के बाद प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा वर्तमान समय में है। सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया जिससे लोगों के बिजली के बिल दुगुना से भी अधिक आ रहा। महंगी बिजली के बाद भी सरकार जनता को चौबीस घंटे बिजली नहीं उपलब्ध करवा पा रही।

भाजपा बताये महादेव सट्टा एप का कमीशन किसके पास जा रहा - कांग्रेस

रायपुर। डबल इंजन की सरकार में महादेव सट्टा एप खुले आम देशभर में चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा बताये महादेव सट्टा एप का कमीशन किस भाजपाई सत्ताधीश के पास आ रहा है। खुले आम सोशल मीडिया प्लेट फार्म, फेसबुक और इंस्ट्राग्राम में खुले आम विज्ञापन चल रहा है क्या इसकी जानकारी सरकार के पास नही है। जो सरकार अपने खिलाफ एक पोस्ट करने पर आम आदमी के एकाउंट पर प्रतिबंध लगवा देती है क्या उस सरकार को महादेव सट्टा एप के विज्ञापन की जानकारी नही है। यह विज्ञापन बताता है कि महादेव सट्टा एप पर भाजपा की राज्य और केन्द्र सरकार दोनों के संरक्षण में चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिस महादेव बैटिंग एप को लेकर कांग्रेस पर झूठा आरोप लगा रही थी भाजपा विधानसभा चुनाव के दौरान ओछी राजनीति कर रही थी, और उक्त एप को आर्थिक बर्बादी का कारण बता रहे थे।

बस्तर के लिए 360° प्लान

टूरिज्म, स्टार्टअप, इंफ्रा और इनोवेशन पर फोकस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल नक्सलवाद के अंत के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया, बल्कि बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट भी सौंपा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का आमंत्रण दिया, जहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि बस्तर समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब शांति स्थापित है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुधार के तहत नए एजुकेशन सिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जबकि इंद्रावती नदी पर बैराज, रेल लाइन और एयरपोर्ट विस्तार से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए बस्तर में अब विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाओं का नया दौर शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने अपने विकास दस्तावेज़ में उल्लेख किया कि एक दशक पहले प्रधानमंत्री द्वारा बस्तर के लिए देखा गया शांति और विकास का सपना अब जमीन पर साकार हो रहा है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब लोगों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद और विकास की नई चमक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से बस्तर को नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र में विश्वास और उत्साह बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विकास ब्लूप्रिंट 'सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज' रणनीति पर आधारित है। इसके तहत बस्तर में बुनियादी सुविधाओं को तेजी से विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के व्यापक जाल के माध्यम से दूर-दराज के गांवों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को 2027 तक पूरा करने के साथ-साथ नई 228 सड़कों और 267 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 61 नई परियोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी की गई है।

ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की योजना है। हर घर तक बिजली पहुंचाने के कार्य तेज होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 45 पोटा केबिन स्कूलों को स्थायी भवनों में बदला जाएगा। युवाओं के लिए 15 स्टेडियम और 2 मल्टीपर्पज हॉल बनाए जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और डॉक्टरों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।

महिला आरक्षण विधेयक पर 'मॉक पार्लियामेंट' का आयोजन

रायपुर। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिन क्षेत्रों और सेक्टरों का नेतृत्व महिलाएं करती हैं, उनका विकास दोगुनी गति से होता है; उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया और शासन-प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी के अत्यंत महत्व को रेखांकित किया। राजीव गांधी भूजल राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक श्री रंजन कुमार जी ने सभी प्रतिभागियों को मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देकर सभी का स्वागत किया।

MY भारत छत्तीसगढ़ के राज्य निदेशक, श्री अर्पित तिवारी ने 'बजट क्वेस्ट 2026' की रूपरेखा प्रस्तुत की, और इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार युवाओं के नेतृत्व वाली गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण और शासन-प्रशासन में अधिकाधिक रूप से परिलक्षित हो रही हैं। मॉक पार्लियामेंट की कार्यवाही के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्री की भूमिका निभाते हुए एक युवा प्रतिनिधि ने सदन में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई विस्तृत बहस और संसदीय विमर्श के पश्चात, इसे सदन में बहुमत से पारित कर दिया गया — जो इस आयोजन का एक ऐतिहासिक और उत्साहवर्धक क्षण रहा। भाग लेने वाले 40 प्रतिनिधियों ने संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लिया, संशोधनों के प्रस्ताव रखे, और विधेयक के कार्यान्वयन तंत्रों पर विचार-विमर्श किया — इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने भारत की विधायी प्रक्रियाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की, और साथ ही निर्वाचित पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व का पुरजोर समर्थन किया। समापन समारोह में सभी 40 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

'झरिया' ने बदली तस्वीर: एल्कलाइन वाटर प्लांट बना महिला सशक्तिकरण का नया मॉडल

एक साल में 35 लाख का टर्नओवर, 15 लोगों को रोजगार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अभिनव पहल सामने आई है। सीएम विष्णु देव साय की मंशानुसार जिला प्रशासन रायपुर और नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) के सहयोग से ग्राम पचेड़ा में स्थापित 'झरिया एल्कलाइन वाटर प्लांट' ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला उद्यमिता का सफल मॉडल बनकर उभरा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" के अंतर्गत गठित शारदा स्व सहायता समूह द्वारा संचालित इस प्लांट का का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा 11 अप्रैल 2025 को किया गया था। स्थापना के महज एक वर्ष के भीतर इस इकाई ने 35 लाख रुपये का टर्नओवर दर्ज किया है और 15 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया है, जिनमें अधिकांश महिलाएं शामिल हैं।

यह हाईटेक प्लांट प्रतिदिन लगभग 5 हजार कांच की बोतल, 10 हजार प्लास्टिक बोतल, 1 हजार जरीकेन और 500 ठंडे जरीकेन पानी उत्पादन की क्षमता रखता है। यहां दो अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, जहां पानी की शुद्धता और पीएच स्तर (8 से 8.5) की नियमित जांच की जाती है। उत्पादित जल को 200 एमएल से 1 लीटर तक की प्लास्टिक और कांच की बोतलों के साथ-साथ 20 लीटर जरीकेन में पैक किया जाता है। 'झरिया' ब्रांड का एल्कलाइन पानी अब मंत्रालय, जंगल सफारी, आईआईएम, नगर निगम रायपुर, जीएसटी कार्यालय, आईआईटी, एनआरडीए, पर्यावास भवन और कलेक्ट्रेट सहित कई प्रमुख संस्थानों में नियमित रूप से आपूर्ति किया जा रहा है। राज्योत्सव-2025, खेलो इंडिया और कुंवरगढ़ महोत्सव जैसे बड़े आयोजनों में भी इसकी सफल सप्लाई की गई है। इस परियोजना से जुड़ी महिलाओं को उनके कार्य के आधार पर प्रति माह 15,000 रुपये तक का मानदेय मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।

एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकली छत्तीसगढ़ की बेटी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जांजगीर-चांपा जिले की युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास को उनके आगामी माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पर्वतारोही सुश्री अमिता श्रीवास से मुलाकात के दौरान कहा कि आगामी 9 अप्रैल को सुश्री अमिता विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के संकल्प के साथ काठमांडू के लिए रवाना हो रही हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं, साहस और आत्मविश्वास की ऊंची उड़ान है।

उन्होंने कहा कि अमिता का यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि यदि संकल्प अटल हो, तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं रहती। प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नए मानक स्थापित कर रही हैं और छत्तीसगढ़ को नई पहचान दे रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमिता श्रीवास ने वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माउंट किलिमंजारो को फतह कर पहले ही अपनी क्षमता और दृढ़ता का परिचय दिया है। उनका यह सतत प्रयास न केवल उपलब्धि है, बल्कि प्रदेश की युवा पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमिता अपने इस साहसिक अभियान में सफलता प्राप्त कर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर देश का तिरंगा फहराएंगी और छत्तीसगढ़ सहित पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगी

शहर का ब्यस्त यातायात होगा तेज और सुव्यवस्थित

राजधानी में इस साल बनेंगे 4 फ्लाईओवर्स

रायपुर। राजधानी रायपुर में इस साल 4 फ्लाईओवर्स के काम शुरू होंगे। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने चारों फ्लाईओवर्स के लिए कुल 360 करोड़ 35 लाख 93 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इन फ्लाईओवर्स के निर्माण से शहर के ब्यस्त यातायात को तेज, स्मूथ और सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। शहरवासी इनके निर्माण की मांग लंबे समय से कर रहे थे। लोक निर्माण विभाग ने शहर के बीच जी.ई. रोड पर गुरू तेज बहादुर उद्यान से तेलीबांधा के नेताजी सुभाष चौक तक फ्लाईओवर के लिए 172 करोड़ 86 लाख 28 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। रायपुर के रिंग रोड क्रमांक-2 में सोनडोंगरी चौक पर ओवरपास के लिए 43 करोड़ 89 लाख 17 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। विभाग ने रायपुर में वी.आई.पी. रोड के फुंडहर चौक में ओवरपास के निर्माण के लिए 56 करोड़ सात लाख 35 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। शहर के अटल पथ एक्सप्रेस-वे पर फुंडहर चौक में ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए भी लोक निर्माण विभाग द्वारा 87 करोड़ 53 लाख 13 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।"राज्य शासन रायपुर में यातायात को तेज, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। शहर में फ्लाईओवर्स और सड़कों के

चौड़ीकरण के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इनसे ट्रैफिक-जॉम में कमी आएगी और लोगों की आवाजाही अधिक सहज होगी। हमारी प्राथमिकता है कि रायपुरवासियों और यहां आने वाले हर व्यक्ति को बेहतर और सुगम यातायात मिले। - अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण"

जिलों में बनेंगी फोरलेन सड़कें, 708 करोड़ मंजूर

यातायात के लिए मजबूत और चौड़ी सड़कें उपलब्ध कराने लोक निर्माण विभाग ने 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस राशि से विभिन्न जिलों में कुल 90.5 किमी फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से प्रमुख सड़कों पर सुगम यातायात और जॉम से मुक्ति के साथ ही यात्रा का समय घटेगा। फोरलेन सड़कों से सुरक्षित यातायात के साथ ही आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। इससे कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में दुर्ग-धमधा-बेमेतरा अंडर ब्रिज से अग्रसेन चौक तक 0.5 किमी फोरलेन मार्ग के लिए तीन करोड़ 41 लाख रुपए, स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आई.आई.टी. जेवरा सिरसा तक 7 किमी फोरलेन सड़क के लिए 20 करोड़ 64 लाख रुपए, मिनी माता चौक से महाराजा चौक-ठगड़ा बांध तक 4.70 किमी फोरलेन मार्ग के लिए 28 करोड़ 58 लाख रुपए तथा महाराजा चौक से बोरसी चौक तक 1.80 किमी फोरलेन सड़क के लिए 23 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन

सीने के इंफेक्शन के बाद मल्टी ऑर्गन फेल्योर बना वजह

दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. आशा भोसले को शनिवार को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. रविवार को आशा भोसले का निधन हो गया. आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने आशा के निधन की जानकारी दी. आशा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. नेता, सेलेब्स सभी लोग उनके निधन पर दुख जता रहे हैं. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, 'मधुर वाणी और अद्वितीय गायकी की प्रतिमूर्ति दीदी आशा भोसले जी ने दशकों तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उनकी आवाज केवल सुरों का संगम नहीं, बल्कि भावनाओं का ऐसा अनकहा रिश्ता है जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है. एक ऐसा जुड़ाव जो हर दिल में सदा जीवित रहेगा. उनके गाए गीत आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही गूंजते रहेंगे.'

आनंद भोसले ने कहा, 'मेरी मां आशा भोसले का आज निधन हो गया है. कल चार बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा.' आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया था कि आशा भोसले को शनिवार रात को चेस्ट इंफेक्शन की वजह से एडमिट करवाया गया था. लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से आशा भोसले का निधन हो गया. आशा भोसले को कई अवॉर्ड से नवाजा गया. उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. 2000 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था. उन्हें दो बार नेशनल अवॉर्ड मिला. उन्हें 1981 और 1986 में सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक गायिका का अवॉर्ड मिला. इसके अलावा उन्हें 7 बार फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 1996 में फिल्म रंगीला के लिए उन्हें फिल्मफेयर स्पेशल अवॉर्ड मिला.2001 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया. 2002 में फिल्म लगान के लिए IIFA Awards मिला. इसके अलावा उन्हें 1987 में नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवॉर्ड मिला. 2000 में (दुबई) सिंगर ऑफ द मिलेनियम और 2002 BBC लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला.

पहला गाना गाते वक्त आशा भोंसले के कांप रहे थे हाथ

छोटी उम्र में पिता को खोया,मां के सपोर्ट से बनीं दिग्गज सिंगर

आशा भोसले ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी और कैसे दिग्गज सिंगर बनीं। एक इंटरव्यू में आशा भोसले ने बताया था कि जब उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया था तब वो महज 10 साल की थीं. उन्हें माइक के सामने गाना था और उस वक्त उनके हाथ पैर कांप रहे थे.क्योंकि, पहले पता ही नहीं था कि माइक क्या होता है.

उनके पिता जी ने रिकॉर्ड करके रखे थे अपने गाने, तो दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसा भी होता है. पहला गाना गाने के बाद उन्हें लगा था कि वो गा सकती हैं. सिर्फ उनकी दीदी ही नहीं बल्कि सभी भाई-बहन गा सकते हैं. आशा भोसले ने आगे कहा था,'पहला गाना गाया, तबसे गा रही हूं और खड़ी हूं. फिल्म लाइन का खड़ा होना ऐसा होता है कि सुबह 10 बजे स्टूडियो पहुंचे तो रात के 10-11 बज जाते हैं. कभी-कभी सुबह के 8 बज जाते हैं. ये माइक की लाइफ विचित्र होती है.' आशा भोसले ने बताया था,'मेरे पिताजी बहुत छोटी उम्र में गोवा से मुंबई भागकर आ गए थे.आकर यहां पर उन्होंने

ड्रामा कंपनी बनाई बलवंत संगीत मंडली, वो उसके मालिक भी थे और काम भी करते थे. हमारी जिंदगी खानाबदोश जैसी रही. तीन महीने यहां-तीन महीने वहां, ऐसे महाराष्ट्र में हम घूमते थे.सर्कस के जैसे शेड लेकर इधर-उधर जाते थे. बहुत मजा था उस वक्त. दूध-मलाई खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था. पिताजी थे तब सब कुछ बहुत अच्छा था. लेकिन, पिता जी के निधन के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

सुरों से सजा आशा भोसले का परिवार

आशा भोसले का जन्म दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था. उनके पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी बच्चों पर आ गई और कम उम्र में ही उन्हें काम शुरू करना पड़ा. उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से ही संगीत की दुनिया में बड़ा नाम थीं और उनकी बहनें उषा मंगेशकर और मीना खादीकार और भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीत से जुड़े रहे. इतने बड़े और नामी परिवार में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन आशा भोसले ने अपने अलग अंदाज और मेहनत से खुद को साबित किया.

उनकी निजी जिंदगी में भी कई उतार-चढ़ाव आए. 16 साल की उम्र में परिवार के अनुमति के बिना उन्होंने गणपत राव भोसले से शादी की, जहां उन्हें मानसिक और शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ी. तीसरी प्रेगनेंसी के समय उन्हें ससुराल से निकाल दिया गया और दोनों 1960 में अलग हो गए. कुछ समय बाद उन्होंने मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन से शादी की, जिनके साथ उनकी जोड़ी ने कई हिट गाने दिए. गणपत राव से उनके तीन बच्चे हेमंत, आनंद और वर्षा है, जिनकी परवरिश उन्होंने अकेले ही की. इतना कुछ सहने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई. 2015 में उन्होंने अपने बेटे हेमंत को खो दिया, जिन्हें कैंसर हुआ था. साथ ही 2012 में उनकी बेटी वर्षा का भी देहांत हो गया. इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार काम करती रहीं. आज उनकी पोती जनाई भोसले भी इस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और संगीत में सक्रिय है.

250 करोड़ रुपये की मालकिन थीं आशा भोसले, कौन होगा संपत्ति का वारिस?

आशा भोसले की नेटवर्थ 200 से 250 करोड़ रुपये है. उनकी आय का मुख्य स्रोत उनका लंबा और सफल संगीत करियर रहा है. उन्होंने दशकों तक हिट गानों और एल्बम्स के जरिए अच्छी कमाई की. इसके अलावा देश-विदेश में होने वाले उनके लाइव शो और म्यूजिकल टूर भी उनकी कमाई का बड़ा जरिया रहे हैं. वहीं, उनके पुराने गानों की डिजिटल स्ट्रीमिंग और रेडियो पर लगातार बजने से उन्हें लागातार रॉयल्टी भी मिलती रहती थी. इसके अलावा आशा भोसले एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन Asha's चलाती थीं. उनके रेस्टोरेंट काफी फेमस हैं. कई शहरों में ये रेस्टोरेंट हैं. गायिका के पास कई लग्जरी कार भी हैं. मुंबई और पुणे में उनकी आलाशीन प्रॉपटी भी हैं. पर्सनल लाइफ में आशा भोसले ने 2 शादियां की. उन्होंने पहली शादी गणपत राव से हुई. हालांकि, 11 साल बाद दोनों अलग हो गए. गणपत राव से आशा भोसले को तीन बच्चे (वर्षा भोसले, हेमंत भोसले और आनंद भोसले) हुए. इसके बाद आशा भोसले ने 1980 में म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन से शादी की. वह आशा भोसले से 6 साल छोटे थे. आशा भोसले और आरडी बर्मन की कोई अपनी संतान नहीं है.

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बांसगीत का सामाजिक सन्दर्भ

डा. सोमनाथ यादव

छत्तीसगढ़ी बांसगीत और गाथाओं में इतिहास और संस्कृति के पृष्ठभूमि में सामाजिक सन्दर्भ उभरता है। यदुवंशियों की अलौकिक वीरता, शरीर सौष्ठव, पहनावा, खानपान, उत्सव और रीति रिवाज सभी में उसका सामाजिक सन्दर्भउभरकर आता है। इनके शौर्य प्रदर्शन के आधार पर विरोचित पहनावा झलकता है। रंग बिरंगी पगड़ी, उसके ऊपर लहराती कलगी, मोर पंख, कौड़ी, कांच से बनी साज सज्जा, लाठी, घुटनों तक कसी और बंधी धोती पर उसका नर्तन, शखों का प्रदर्शन, प्राचीन और - पारम्परिक युद्ध कला को जीवंत कर जाता है।

इसी तरह प्राचीन मड़ई का सम्बन्ध वेद की इंद्र ध्वज परंपरा से जोड़ा जाता है। इसमें मोर पंख आर्य संस्कृति, कौड़ी द्रविड़ और मुर्गा आदिवासी या निषाद संस्कृति का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति में तीनों तत्व समाहित हैं। बांसगीत और लोक कथाओं में लोक कीर्तन परंपरा की झलक मिलती है। बांस से लोक वाह्य बना कर उसे बजाना, बंशी वादन के भी पहले की परंपरा प्रतीत होती है। इसलिए इसमें आध्यात्म, इतिहास और संस्कृति के बहाने जातीय गौरवगाथा का प्रदर्शन होता है। बांसगीत की यह विशिष्टता है कि इसमें जहां सार्वदेशिक और प्रख्यात चरित्रों का महिमामंडित गान समाहित हैं, वहीं क्षेत्रीय और ग्रामीण विभूतियों के कार्यों का चित्रण है।

इतिहास के पन्नों में कांकेर रियासत

निर्मलकांत श्रीवास्तव

कांकेर का प्राचीन नाम शिलालेख व ताम्र पत्रों में कांकेर या काकरय लिखा हुआ है। यदि यह नाम संस्कृत के काक्स का अपभ्रश हो तो इसका अर्थ होता है कौए का शोर वाला स्थान। इससे स्पष्ट होता है कि पहले समय में यहां कौओं का बड़ा शोरगुल होता रहा हो। इसके उत्तरी भाग में दुर्ग, पूर्व में रायपुर जिला, दक्षिण बस्तर और पश्चिम में चांदा जिला। कांकेर राजवंश सोमवंशी क्षत्रिय था। किवंदती है कि राज्य के प्रथम अधिश्वर वीर कांहरदेव जगन्नाथपुरी के राजा थे। पर कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के कारण उन्हें अपना राज्य त्याग करना पड़ा। स्वास्थ्य लाभ की तलाश में प्रवास करते हुए वे सिहावा आ पहुंचे, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम प्राचीन समय से रहा है। और वे सिहावा की जनता के अनुरोध पर यहां राज्य करने लगे, जो 18 पौढ़ी तक इस वंश में चलता रहा। पर सिहावा में प्राप्त एक शिलालेख से जो शक संवत 1114 में उत्कीर्ण किया गया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि वहां इस वंश का राज्य कुछ समय तक अवश्य रहा होगा। कहते हैं कि इस घराने के तीसरे राजा ने कांकेर परगना को अपने राज्य में सम्मिलित कर सिहावा से कांकेर राजधानी उठा लाया, जो प्राचीन काल में कंकन कहलाता था।

छत्तीसगढ़ की जेल में जन्मी थी ' पुष्प की अभिलाषा'

स्वराज करुण

प्रसिद्ध कर्मवीर कवि पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी की लोकप्रिय कविता 'पुष्प की अभिलाषा' का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित केन्द्रीय जेल में हुआ था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शनिचरी मैदान में एक विशाल आम सभा हुई थी. जहां चतुर्वेदी जी ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की बत्ती जल्द गुल होने और स्वतंत्रता का सूर्योदय जल्द होने का ऐलान किया था। इस पर तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

चतुर्वेदी जी 5 जुलाई 1921 से एक मार्च 1922 तक लगभग 8 महीने बिलासपुर के सेन्ट्रल जेल में कारावास में रहे। वहीं उन्होंने 'पुष्प की अभिलाषा शीर्षक अपनी प्रसिद्ध कविता की रचना की, जिसमें एक पुष्प के माध्यम से देशवासियों की स्वतंत्रता की चाहत और मातृभूमि की आजादी के लिए अपना शीश चढ़ाने की तीव्र उत्कंठा प्रकट की गयी है। यानी यह कविता लगभग सौ साल से भी कुछ पहले कवि माखनलाल चतुर्वेदी के कारावास काल में उनके हृदय से निकली थी।

चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को वर्तमान मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के ग्राम बाबई में हुआ था। उनका निधन 30 जनवरी 1968 को हुआ । चतुर्वेदी जी कवि होने के साथ-साथ लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने वर्ष 1906 में अध्यापक के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, लेकिन लोकमान्य बालगंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने 'प्रभा' 'प्रताप' और 'कर्मवीर 'नामक पत्रिकाओं का भी सम्पादन किया। पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी ने सैकड़ों कविताएँ लिखीं। देशप्रेम से परिपूर्ण उनकी अधिकांश रचनाओं का मूल स्वर प्रगतिवादी है। आजादी के बाद चतुर्वेदी जी को भारत सरकार ने वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1963 में पद्मभूषण अलंकरण से सम्मानित किया था। उनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया।

साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें अपनी काव्य कृति 'हिमतरंगिनी' पर प्रदान किया गया था। मध्यप्रदेश सरकार ने 16-17 जनवरी 1965 को उनके सम्मान में खंडवा में नागरिक अभिनन्दन समारोह का भी आयोजन किया था। सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी. लिट् की मानद उपाधि से नवाजा। उनकी लगभग 100 वर्ष पहले की इस बेहद लोकप्रिय कविता की अमिट पंक्तियों को आइए, एक बार फिर मन ही मन गुनगुनाएं

चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं।
चाह नहीं, प्रेमी-माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं।।
चाह नहीं, सम्राटों के शव पर हे हरि, डाला जाऊं।
चाह नहीं, देवों के सिर परचहूँ भाग्य पर इठलाऊं।।
मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वौर अनेक।।

बस्तर अंचल में गाए जाते हैं चइत परब गीत

डा. पी. सी. लाल यादव

छत्तीसगढ़ में जनजातियों की बहुलता है। यह जनजातियां आज भी अपनी आदिम प्रवित्तियों और परंपराओं के साथ घने जंगलों में निवास करती हैं। इनके रीति रिवाज, उत्सव, पर्व, रहन सहन, गीत संगीत लोगों के लिए कौतूहल और आकर्षण के विषय हैं। यह भोलेभाले, सहज सरल और आत्मीय होते हैं। धरती की तरह सहनशील, पर्वत की धैर्यवान और गंगा जल की तरह पवित्र और चरित्र वान। छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल तो आदिम संस्कृतियों का भंडार है। यहां मुरिया, माड़या, भतरा, हल्बा आदि जनजातियां निवास करती हैं, इनमें गीत संगीत और नृत्य की विशिष्ट परंपराएं हैं। इसमें चैत्र माह में चइत परब गीत गाने की परंपरा है -

ए लेकी चो खेलुक जातोर, केबइ नी फिटे...
फिटू आय कसन जाले, ए चंपा फूलों, ए मोंगरा फूलों...
सरली रे जुआन लेकी बाय जन जालो...
ए लेका चो बुलुक जाटोर, केवइ नी फिटे... फिटू आय कसन जाले, ए डूमर फूलो ए सेमर फूलो...

बड़े डोंगर के प्राचीन धरोहरों में नकटी देवरली

घनश्याम नाग

हल्बी भाषा में मंदिर को देवरली कहा जाता है और जिसकी नाक कटी हो उसे नकटी। भैंसा दोंद डोंगरी के दक्षिण में तालगुंडरा के नीचे एक प्राचीन मंदिर के भगनावशेष बिखरे पड़े हैं। प्रस्तर खंडो के इस मंदिर के सम्बन्ध में जनश्रुति है कि माई दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तभी से नकटी देवरली मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ। माई जी का मंदिर बन कर तैयार हो गया, लेकिन अब देख कर लोग शिव मंदिर का अनुमान लगाते हैं जो अधूरा रह गया। मंदिर बनाने में पिछड़ जाने के कारण निर्माणकर्ताओं ने शर्म महसूस किया और इसे अधूरा ही छोड़ दिया। तब से इस बिखरे मंदिर को नकटी देवरली कहते हैं, उपहास और उपेक्षा से यह कलात्मक मंदिर उजाड़ हो गया। तरासे गए प्रस्तर खंड आसपास बिखरे पड़े हैं, गर्भ गृह का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। लेकिन किसी देवी देवता का विग्रह स्थापित नहीं है इसलिए यहां कभी पूजा या जातरा भी आयोजित नहीं की जाती। अब इस प्राचीन धरोहर पर बड़ी बड़ी झाड़यां ऊग आई हैं, जिससे इसके प्राचीन भव्यता का अंदाजा लगाना आसान नहीं है।

जल्द हाईप्रोफाइल 'कसीनो'....

राजधानी रायपुर में भी 'कसीनो' खोलने की कवायद तेज

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब जल्द जल्द हाईप्रोफाइल जुआ घर यानि कि 'कसीनो' खोलने की कवायद तेज हो गई है। देसी शब्दों में समझे तो हाईप्रोफाइल जुआ घर। जहां जाकर आप जुआ खेल सकते हैं। गोवा जैसे लग्जरी होटलों के साथ स्थानीय कारोबारी और तक़रीबन 12 हाईप्रोफाइल व्हाइट कॉलर्स कसीनो खोलने वाले हैं। कुछ ने सुझाव दिए कि गोवा की तर्ज पर यहां भी कसीनो खोला जाए। भारत समेत छत्तीसगढ़ में जुआ पर्यटकों के लिए एक अच्छा मनोरंजन स्थल बनने की संभावना और छत्तीसगढ़ का पैसा यहीं रहे यह सोचकर भी जल्द मंजूरी मिल सकती है। भारत सरकार ने देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लाइसेंस प्राप्त और प्रतिष्ठित 'कसीनो' को बढ़ावा दिया है। यहाँ भारत के 10 सबसे बड़े 'कसीनो' की सूची से साफ जाहिर है कि अब यह बुराई नहीं तेज़ी से बढ़ता कारोबार बन गया है।

कारोबारी और 12 हाईप्रोफाइल व्हाइट कॉलर्स होंगे पार्टनर

खेलने के शौकीन गोवा-श्रीलंका में गंवा-लुटा रहे करोड़ों रूपये

'कसीनो' खुला तो अवैध जुआ-सट्टे का धंधा हो जायेगा ठप्प

छत्तीसगढ़ को मिलेगा राजस्व बढ़ेगा पर्यटकों के लिए विकल्प

कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लाइसेंस प्राप्त हैं प्रतिष्ठित 'कसीनो'

शहर सत्ता/रायपुर। सब कुछ सोची-समझी योजना के मुताबिक हुआ तो महज डेढ़ महीने में राजधानी रायपुर में भी 'कसीनो' परंपरा की अच्छी शुरुआत होगी। इसके लिए शहर के दो बड़े कारोबारी और आधा दर्जन से ज्यादा राजनेताओं की मिलीभगत से सरअंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली से लेकर लोकल स्तर में भी तैयारियां अंतिम चरण में है। बस हरी झंडी का इंतजार है और छत्तीसगढ़ से गोवा, श्रीलंका, बैंकॉक-पट्टाया जाकर पैसा लगाने वाले शौकीनों को अब रायपुर में ही आवभगत सत्कार के साथ दांव लगाने की सुविधा मिलने लगेगी।

हमारा पैसा जायेगा बाहर

छत्तीसगढ़ से 'कसीनो' में दांव लगाने वाले शौक़ीन हर हफ्ते गोवा, श्रीलंका समेत ऑनलाइन तकरीबन 200 करोड़ रूपये लुटाते हैं। महीने में ये आंकड़ा तक़रीबन 1200 करोड़ तक पहुंच जाता है। महज शनिवार और और रविवार 2 दिन में छत्तीसगढ़ से कसीनो में 75 करोड़ तक खपाने वाले हैं। ऐसे में रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में अवैध जुआ, सट्टे का धंधा भी आर्थिक, सामाजिक क्षति पहुंचा है। यहां का पैसा, मोटा राजस्व और आधुनिक वैध तरीकों से व्यवस्थित कारोबार के लिए ;कसीनो' बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

जगह चिन्हांकित, पार्टनर तय

सूत्रों का दावा है कि एमसीएक्स का पुराना माहिर युवा कारोबारी और उसके साथ छत्तीसगढ़ के चंद राजनेता, व्यापारियों की पार्टनरशिप है। कसीनो के लिए कल्पवृक्ष में जगह भी चिन्हांकित की गई है। सर्वसुविधायुक्त कसीनो बिल्डिंग और दांव लगाने के शौकीनों की सुरक्षा के साथ सुविधाएं भी मुहैया होगी। सेंट्रल से लाइनअप होते ही राज्य से अनुमति में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

कसीनो में क्या-क्या होता है?

कैसिनो में कई तरह के जुए के खेल होते हैं, जिनमें से कुछ में कौशल की भी आवश्यकता होती है। आम खेलों में क्रैप्स , रूलेट , बैकरेट , ब्लैकजैक और वीडियो पोकर शामिल हैं।

कैसिनो क्या है

कैसीनो इतालवी मूल का है; मूल कासा का अर्थ है एक घर। कसीनो शब्द का अर्थ एक छोटा देश विला, समरहाउस या सामाजिक क्लब हो सकता है। 19वीं शताब्दी के दौरान, कैसीनो में अन्य सार्वजनिक भवनों को शामिल किया गया जहां आनंददायक गतिविधियां होती थीं; इस तरह की इमारतों को आमतौर पर एक बड़े इतालवी विला या पलाज़ो के आधार पर बनाया गया था, और नृत्य, जुआ, संगीत सुनने और खेल सहित नागरिक शहर के कार्यों की मेजबानी के लिए उपयोग किया जाता था।

भारत का सबसे बड़ा कैसीनो कहां है?

भारत के सर्वश्रेष्ठ कैसीनो के रूप में मूल्यांकित, डेल्टिन रॉयल गोवा की हर यात्रा पर अवश्य देखने योग्य स्थान है! 50,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला, डेल्टिन रॉयल में लगभग 1000 गेमिंग स्थान और एक शानदार पार्टी या भव्य समारोह के लिए उत्तम स्थल हैं।

सटोरियों का होगा जिला बदर

आर्थिक अपराध पर लगाम लगाने पुलिस कमिश्नर ने क्षेत्र में सक्रिय ऐसे सटोरिया व जुआ फड़ संचालित करने वाले जो पकड़े जाने के बाद मी जुआ, सट्टा संचालित करते हैं, उनकी पहचान करने के निर्देश दिए है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय ऐसे अर्थिक अपराध से जुड़े अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई करेगा।

संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर कार्यालय के आदेश के अनुसार सटोरियों तथा जुआ फड़ संचालित करने वाले अपराधियों की संपत्ति का विवरण देने कहा गया है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार जुआ, सट्टा संचालित करने वाले अपराधियों की आने वाले दिनों में संपत्ति कुर्की की कार्रवाई न्यायालय के माध्यम से की जाएगी।

भारत के 10 सबसे बड़े कैसिनो

1. विनर्स कैसीनो और हैसिएंडा डी ओरा: विनर्स कैसीनो हैसिएंडा डी ओरा में स्थित है और इसमें 150 कैसीनो स्लॉट मशीनें, वीडियो और पोकर गेम हैं। यह गोवा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है।

2. डेल्टिन रॉयल कैसीनो: डेल्टिन रॉयल कैसीनो दमन में स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैसीनो रिसॉर्ट है, जो 10 एकड़ में फैला है और इसमें 60,000 वर्ग फुट का गेमिंग क्षेत्र है। डेल्टा कॉर्प के स्वामित्व वाली यह कंपनी मानती है कि कैसीनो मुंबई और गुजरात दोनों से रणनीतिक रूप से स्थित है और इसे गेमर्स का स्वर्ग भी माना जाता है।

3. डेल्टिन जैक: बेहद लोकप्रिय डेल्टिन जैक में 3-कार्ड पोकर, रूलेट, बैकर्ट अंदर-बाहर सहित 350 विभिन्न गेमिंग विकल्प हैं, जो मेहमानों को एक असाधारण गेमिंग अनुभव प्रदान करते हैं।

4. कैसीनो कार्निवल: गोवा में स्थित, यह कैसीनो चार भव्य डेक में फैला हुआ है और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन के बेहतरीन पैकेज उपलब्ध कराता है। कैसीनो कार्निवल में प्रसिद्ध स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कलाकारों द्वारा भी शानदार प्रस्तुतियां दी जाती हैं।

5.कैसीनो प्राइड : गेमर्स के लिए स्वर्ग के समान, कैसीनो प्राइड एक समय में 500 से अधिक मेहमानों को रोमांचक गेमिंग अनुभव प्रदान करता है। मांडोवी नदी के जल पर तैरता हुआ 30,000 वर्ग फुट का यह कैसीनो गेमर्स को एक शानदार अनुभव देता है।

6. कैसीनो पर्ल: दक्षिण गोवा का सबसे बड़ा कैसीनो, कैसीनो पर्ल में ताई-साई, ब्लैक जैक, रूलेट, बैकारेट और स्लॉट मशीन जैसे रोमांचक खेल उपलब्ध हैं। कैसीनो पर्ल गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 15 मिनट की दूरी पर स्थित है और कई पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है।

7. कैसिनो पाम्स: गोवा के शानदार ला कैलिप्सो होटल में स्थित कैसिनो पाम्स, समुद्र तट पर परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और लाइव गेमिंग का आनंद लेने के लिए सबसे तनावमुक्त कैसिनो में से एक है।

8. कैसिनो पैराडाइज: गोवा के सबसे बड़े और शानदार कैसिनो में से एक, यह 5,000 वर्ग फुट का कैसिनो एक अद्वितीय गेमिंग अनुभव के लिए डिज़ाइन और सजाया गया है। कैसिनो पैराडाइज, गोवा के कैसिनो होटलों में लोकप्रिय, शानदार नियो मैजेस्टिक का एक हिस्सा है।

9. ड्यून्स - द कैसिनो: गोवा के ज़ूरी व्हाइट सैंड्स रिसॉर्ट में स्थित, इस कैसिनो में रूलेट, ब्लैक जैक, मिनी फ्लश रमी और अन्य खेलों सहित कई प्रकार के गेम उपलब्ध हैं।

10. चांसेस कैसिनो: गोवा के तटवर्ती कैसिनो में एक अग्रणी, चांसेस कैसिनो पणजी, गोवा के एक 5 सितारा बुटीक होटल का हिस्सा है। बेहद शानदार माहौल में पारंपरिक गेमिंग की पेशकश के लिए लोकप्रिय, चांसेस कैसिनो पर्यटकों को उनके प्रवास के दौरान तरोताज़ा महसूस करने में मदद करता है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27